



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, अप्रैल 17—अप्रैल 23, 2005, शनिवार/चैत्र 27—वैशाख, 3, 1927
No. 17] NEW DELHI, APRIL 17—APRIL 23, 2005, SATURDAY/CHAITRA 27—VAISAKHA 3, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2005

सा०का०नि० 128.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में कम्प्यूटर आंकड़े प्रक्रमणकर्ता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, (कम्प्यूटर आंकड़े प्रक्रमणकर्ता), (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कम्प्यूटर ऑफ़िसेर प्रक्रमणकर्ता	01(एक)*(2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	4500-125-7000 रु.	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
---	---	--	--	-------------------------------

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए भी विहित सीमा के अनुसार शिथिल की जा सकती है।)	नहीं	आवश्यक : (i) किसी एक विषय के रूप में गणित या सांख्यिकी सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में उपाधि पत्र।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

(12)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन द्वारा तथा इसके विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

केन्द्रीय/राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों के उन अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन किया जा सकेगा;

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिसने 4000-6000 रुपये के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्षों तक नियमित सेवा की है; या

(iii) जिसने 3200-4900 रुपये के वेतनमान वाले पदों पर 10 वर्षों तक नियमित सेवा की है; या

(ख) जिसके पास स्तंभ 8 में विहित सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं और अनुभव है। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

विभागीय प्रोन्नति समिति (केवल पुष्टि करने के लिए) :

लागू नहीं होता

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. चिकित्सा अधीक्षक/संकायाध्यक्ष : | —अध्यक्ष |
| 2. विभागाध्यक्ष (सम्बद्ध) | —सदस्य |
| 3. उप निदेशक (प्रशासन) | —सदस्य |
| 4. कार्यालय का प्रधान | —सदस्य |

[फा. सं. ए-12018/7/2001-आर.आर./एम.ई.-IV]

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 11th April, 2005

G.S.R. 128.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Computer Data Processor in the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, (Computer Data Processor) (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2005.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Computer Data Processor	01(one)* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4500-125-7000.	Not applicable	25 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years and also for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons as per limit prescribed in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
7	8		9		10
No	Essential : (i) Bachelors degree from a recognized University with Mathematics or Statistics as one of the subjects. (ii) Diploma in Computer application from a recognized Institute. Note 1 :- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.		Not applicable		Two years for direct recruits.

8	9	10
<p>Note 2 :-Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in case of candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption, and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
By deputation (including short-term contract)/Absorption failing which by direct recruitment.	<p>Deputation (including short-term contract) or Absorption from officers of the Central/State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies;</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) with 5 years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 4000—6000 or equivalent; or</p> <p>(iii) with 10 years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 3200—4900; and</p> <p>(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits at column 8.</p> <p>(The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
<p>Departmental Promotion Committee (for confirmation only) :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Medical Superintendent/Dean—Chairman 2. Head of Department (Concerned)—Member 3. Deputy Director (Administration)—Member 4. Head of Office—Member 	Not applicable.

1179 GT/2005-2

[F. No. A-12018/7/2001-RR/ME-IV]

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2005

सा. का. नि. 129.—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 318 तारीख 8 सितम्बर, 2004 को भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 25 सितम्बर, 2004 को पृष्ठ 185 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

"खंड (2)(ख)(ii) 4 के अधीन" "शरीर रचना विज्ञान विभाग" के स्थान पर "सामुदायिक चिकित्सा विभाग" पढ़ें।

[सं. वी. 24011/8/2002-एम.ई. डेस्क-II]

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th April, 2005

G.S.R. 129.—In notification of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) number G.S.R. 318 dated 8th September, 2004 published in Part-II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India dated the 25th September, 2004 at page 1858, the following corrections be made :—

Under clause (2) (b) (ii) 4", for "Professor and Head of the Anatomy Department" read "Professor and Head of the Community Medicine Department".

[No. V. 24011/8/2002 ME Desk-III]

S. K. MISHRA, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2005

सा. का. नि. 130.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, आशुलिपिक श्रेणी I, II और III भर्ती नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, आशुलिपिक श्रेणी I, II और III भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, आशुलिपिक श्रेणी I, II और III भर्ती नियम, 2004 में—

(1) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5 शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,

वहां वह आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को आशुलिपिक श्रेणी I (समूह "ख") (अराजपत्रित) के पदों के लिए किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, शिथिल कर सकेगी किन्तु इन नियमों में आशुलिपिक श्रेणी II और III के समूह "ग" के पदों के लिए इस खंड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने में आयोग से ऐसा परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।"

(2) अनुसूची में,—

(क) आशुलिपिक (श्रेणी I) के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ 12 में, "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन मद (क) में उपमद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपमद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(iii) मूल काडर या विभाग में 4000—6000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो।"

(ख) आशुलिपिक (श्रेणी II) के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने स्तंभ 12 में "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।"

(ग) आशुलिपिक (श्रेणी III) के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने,—

(i) स्तंभ 2 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"3* (तीन) (2004)

*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है),"

(ii) स्तंभ 13 में प्रविष्ट "समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति के लिए—1. अपर विकास आयुक्त या संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा), स्थापना-I अनुभाग का भारसाधक है—अध्यक्ष" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)

1. अपर विकास आयुक्त या संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा), स्थापना-I अनुभाग का भारसाधक—अध्यक्ष"।

[सं. 12018/2/2002-डीसी (एचएल) स्थापना-I]

एस० के० सामल, अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

टिप्पण :— मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 58, तारीख 12 फरवरी, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 21 फरवरी, 2004 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Development Commissioner for Handlooms)

New Delhi, the 12th April, 2005

G.S.R. 130.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, Stenographer Grades-I, II and III Recruitment Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, Stenographer Grades-I, II and III Recruitment (Amendment), Rules 2005;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, Stenographer Grade-I, II and III Recruitment Rules, 2004,—

(1) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely :—

"5. Whether the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of the rules with respect to any class or category of persons for the posts of Stenographer Grade-I (Group-'B' Non-Gazetted) in these rules but such consultation with the Commission on exercising the powers delegated by this clause will not be necessary for the Group-'C' posts of Stenographers Grade-II and III in these rules."

(2) In the schedule,—

(a) against serial number 1 relating to the post of Stenographer (Gr.-I), in column 12, under the heading "Deputation", in item (a), after sub-item (ii), the following sub-item shall be added, namely :—

"(iii) With ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 4000-6000 or equivalent in the parent cadre or Department"

(b) against serial No. 2 relating to the post of Stenographer (Grade-II), in column-12 under the heading "promotion" after the entry, the following Note shall be inserted, namely :—

"Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service".

(c) against serial number 3, relating to the post of Stenographer (Gr.-III),—

(i) in column 2, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"3* (three) (2004)

*(Subject to variation dependent on workload)";

(ii) in column 13, for the entry, "1. Additional Development Commissioner or Joint Development Commissioner (Handlooms) In-charge of E-I Section—Chairman" the following entry shall be substituted, namely :—

"Group—'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—

1. Additional Development Commissioner or Joint Development Commissioner (Handlooms) In-charge of Estt.-I Section—Chairman".

[No. 12018/2/2002-DC (HL)/Estt.-I]

S. K. SAMAL, Addl. Development Commissioner (Handlooms)

Note : The principal rules vide notification number G.S.R. 58 dated the 12th February, 2004, were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (i) dated the 21st February, 2004.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

सा. का. नि. 131.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, हिन्दी अधिकारी भर्ती नियम, 1983 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती संशोधन नियम, 2005 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, हिन्दी अधिकारी भर्ती नियम, 1983 में,—
(1) आरंभिक पैरा में और नियम 1 के उपनियम (i) में “हिन्दी अधिकारी” दोनों शब्दों के स्थान पर “सहायक निदेशक (राजभाषा)” क्रमशः शब्दों और कोष्ठकों को रखा जाएगा।
(2) अनुसूची के स्तंभ 12 में खंड (क) में शीर्षक प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति के अधीन मद (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—
“(iii) 5000-150-8000 रु. के वेतनमान या समतुल्य में छह वर्ष नियमित सेवा की हो”।

[फा. सं. 21/7/98-जी डब्ल्यू-1]

सोहन एस० सैनी, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 421, तारीख 4 जून, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन संख्या सा. का. नि. 455 तारीख 18 नवंबर, 2000 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 13th April, 2005

G.S.R. 131.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board Hindi Officer Recruitment Rules, 1983, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board Assistant Director (Official Language) Recruitment Amendment, Rules 2005;
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Ground Water Board Hindi Officer Recruitment Rules, 1983,—
(1) In the opening paragraph and in rule 1, in sub-rule (1), for the words “Hindi Officer” at both the places, the words and brackets “Assistant Director (Official Language)” shall respectively be substituted;
(2) In the Schedule, in column 12, under the heading ‘Promotion/Deputation’, in clause (a), for item (iii) and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—
“(iii) with six years regular service in posts in the scale of pay Rs. 5000-150-8000 or equivalent; and”.

[F. No. 21/7/98-GW. I]

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number GSR 421 dated 4th June, 1983 and subsequently amended vide number GSR 455 dated 18th November, 2000.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2005

सा. का. नि. 132.—केन्द्रीय सरकार, काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम काफी बोर्ड साधारण भविष्य निधि नियम, 2005 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषा : (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) “अधिनियम” से काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) अभिप्रेत है;

- (ख) "लेखाधिकारी" से बोर्ड का लेखाधिकारी अभिप्रेत है;
- (ग) "बोर्ड" से अधिनियम के अधीन गठित कॉफी बोर्ड अभिप्रेत है;
- (घ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ङ) "निधि" से बोर्ड द्वारा गठित और स्थापित साधारण भविष्य निधि अभिप्रेत है;
- (च) "कर्मचारी" से बोर्ड का वेतनभोगी अधिकारी या कर्मचारी अभिप्रेत है उस व्यक्ति से भिन्न जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में है जिसकी सेवाएं बोर्ड को उधार दी गई हैं या अंतरित की गई हैं;
- (छ) "परिलब्धियों" से मूल नियमों में यथा परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन या निर्वाह अनुदान अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत वेतन के उपयुक्त मंहगाई वेतन, छुट्टी वेतन या निर्वाह अनुदान, यदि ग्राह्य हो, और विदेश सेवा के संबंध में प्राप्त वेतन की प्रकृति का कोई पारिश्रमिक भी सम्मिलित है;
- (ज) "कुटुंब" से अभिप्रेत है,—

(i) पुरुष अभिदाता की दशा में, अभिदाता की पत्नी या पत्नियां, माता-पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहन, मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे तथा जहां माता-पिता में से कोई जीवित नहीं है, पैतृक पितामह या पितामही :

परन्तु यदि कोई अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी का उससे न्यायिक पृथक्करण हो गया है या उस समुदाय की स्वीय विधि जिसकी वह पत्नी है, भरण पोषण की हकदार है तो वह तुरंत उन मामलों में जिनमें ये नियम लागू होते हैं, अभिदाता के परिवार की सदस्य नहीं रह जाएगी या जब तक कि अभिदाता तत्पश्चात् लेखाधिकारी को लिखित में इसकी सूचना नहीं दे देता, तब तक वह उस परिवार की सदस्य बनी रहेगी;

(ii) महिला अभिदाता की दशा में पति, माता-पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहन, मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे तथा जहां माता-पिता में से कोई जीवित नहीं है, पैतृक पितामह या पितामही :

परन्तु यदि अभिदाता लेखाधिकारी को लिखित में सूचना देकर अपने पति को अपने परिवार से अपवर्जित करने की इच्छा व्यक्त न करे तो पति इसके पश्चात् इन नियमों से संबंधित इन मामलों में अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा जब तक कि अभिदाता लिखित सूचना द्वारा ऐसी सूचना को रद्द न कर दे।

टिप्पण : "बच्चे" से कोई वैध बच्चा अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत कोई दत्तक बच्चा भी है, जहां अभिदाता या प्रतिपाल्य को शासित करने वाली स्वीय विधि संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8) के अधीन दत्तक ग्रहण मान्यताप्राप्त है, जो कर्मचारी के साथ रहता है और कुटुंब के सदस्य के रूप में उसे समझा जाता है और जिसके लिए कर्मचारी अपने प्राकृतिक उत्पन्न बच्चे के रूप में उसे वहीं प्रास्थिति देने के लिए कोई वसीयत करता है;

(छ) "छुट्टी" से मूल नियमों या सिविल सेवा विनियम या पुनरीक्षित नियम, 1933 द्वारा मान्यताप्राप्त कोई छुट्टी अभिप्रेत है;

(ज) "वर्ष" से कोई वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किसी अन्य पद का जिसे भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) या मूल नियमों में परिभाषित किया गया है उसी रूप में प्रयोग किया जाएगा जिसमें वह परिभाषित है।

3. निधि का गठन.—(1) निधि रूपों में रखी जाएगी।

(2) इन नियमों के अधीन निधि में संदत्त सभी रकमें "साधारण भविष्य निधि" नामक खाते की बहियों में जमा की जाएंगी।

(3) वे रकमें जिनका संदाय इन नियमों के अधीन संदाय हो जाने के छः महीनों के पश्चात् नहीं लिया गया है, वर्ष के अंत में "निकषों" में अंतरित हो जाएंगी और निकषों के संबंध में सामान्य नियमों के अधीन समझी जाएगी।

4. निधि का प्रबंध.—(1) निधि बोर्ड में निहित होगी और उसका प्रबंध कार्यकारिणी समिति या अध्यक्ष द्वारा उस सीमा तक जिस तक बोर्ड की ओर से कार्यकारिणी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, किया जाएगा।

(2) निधि के प्रबंध के संबंध में बोर्ड का विनिश्चय सदस्यों के ऊपर आबद्धकर होगा।

5. पात्रता की शर्तें.—(1) एक वर्ष की निरंतर सेवा के पश्चात् बोर्ड के सभी अस्थायी कर्मचारी, सभी पुनर्नियोजित पेंशनभोगी (उनसे भिन्न जो अंशदायी भविष्य निधि में प्रवेश के लिए पात्र हैं) और सभी स्थायी कर्मचारी निधि में अभिदाय करेंगे।

(2) पुनर्नियोजित पेंशनभोगी अपने विकल्प पर साधारण भविष्य निधि में अभिदाय कर सकेंगे।

टिप्पण 1 : इस नियम के प्रयोजन के लिए प्रशिक्षु और परीक्षाधीन व्यक्ति अस्थायी कर्मचारी समझे जाएंगे।

टिप्पण 2 : ऐसा कोई अस्थायी कर्मचारी, जो मास के मध्य में वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करता है वह पश्चात्पूर्वी मास से निधि में अभिदाय करेगा।

टिप्पण 3 : (ऐसे अस्थायी कर्मचारी जिसके अंतर्गत प्रशिक्षु और परीक्षाधीन व्यक्ति भी हैं) जो नियमित रिक्तियों के प्रतिनियुक्त किए गए हैं, और जिनके एक से अधिक वर्ष निरंतर चलने की संभावना है, वे एक वर्ष की सेवा पूरा करने से पूर्व किसी भी समय साधारण भविष्य निधि में अभिदाय कर सकेंगे।

6. नामनिर्देशन.—(1) अभिदाता निधि में प्रवेश करते समय लेखाधिकारी को एक ऐसा नामनिर्देशन भेजेगा जिसमें उसकी मृत्यु की

स्थिति में उसके नाम में संदेय होने से पूर्व या संदेय होने पर संदाय न की गई उसके नाम जमाराशि को एक या अधिक व्यक्तियों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हो :

परन्तु जहां कोई अभिदाता अवयस्क है तो उससे उसके वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर ही नामनिर्देशन करने की अपेक्षा की जाएगी :

परन्तु यह और कि कोई ऐसा अभिदाता जिसका नामनिर्देशन करते समय कुटुंब है तो वह ऐसा नामनिर्देशन केवल अपने कुटुंब के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में करेगा :

परन्तु यह भी कि अभिदाता द्वारा किसी अन्य भविष्य निधि की बाबत जिसके लिए वह इस निधि में प्रवेश करने से पूर्व अभिदाय कर रहा था, किए गए नामनिर्देशन, यदि ऐसी अन्य निधि में उसकी जमा रकम, उसके प्रत्यय में अंतरित कर दी गई है तो उसे इस नियम के अधीन सम्यक् रूप से किया गया नामनिर्देशन समझा जाएगा जब तक कि वह इस नियम के अनुसार नामनिर्देशन नहीं करता है।

(2) यदि अभिदाता उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्ति को नामनिर्देशित करता है तो वह नामनिर्देशन में प्रत्येक नामनिर्देशिनी को संदेय रकम या अंश को ऐसी रीति में विनिर्दिष्ट करेगा जिससे कि किसी भी समय निधि में उसकी संपूर्ण जमाराशि आ सके।

(3) प्रत्येक नामनिर्देशन पहली अनुसूची में किए गए प्ररूपों में किया जाएगा।

(4) (i) कोई अभिदाता किसी भी समय लेखाधिकारी को लिखित में सूचना भेजकर किसी नामनिर्देशन को रद्द कर सकेगा।

(ii) अभिदाता ऐसी सूचना के साथ या पृथक् रूप से इस नियम के उपबंधों के अनुसार किए गए नए सिरे से नामनिर्देशन को भेजेगा।

(5) कोई अभिदाता नामनिर्देशन में निम्नलिखित उपबंध करा सकेगा—

(क) किसी विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिनी की बाबत, उसके अभिदाता की मृत्यु की दशा में उस नामनिर्देशिनी को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अंतरित हो जाएंगे जो नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु ऐसा अन्य व्यक्ति या ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि अभिदाता के अपने कुटुंब के अन्य सदस्य है, तो ऐसा अन्य सदस्य या ऐसे अन्य सदस्य होंगे।

(ख) जहां अभिदाता खंड (क) के अधीन एक से अधिक व्यक्ति के लिए ऐसे अधिकार प्रदत्त करता है तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को संदेय रकम या अंश ऐसी रीति में विनिर्दिष्ट करेगा जिसमें नामनिर्देशिनी को संदेय संपूर्ण रकम आ सके।

(6) ऐसे नामनिर्देशिनी की मृत्यु के तुरंत पश्चात् जिसकी बाबत उपनियम (5) के खंड (क) के अधीन नामनिर्देशन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है, अभिदाता लेखाधिकारी को इस नियम के उपबंधों के अनुसार नए सिरे से नामनिर्देशन करते हुए, उक्त नामनिर्देशन को रद्द करने की लिखित में सूचना भेजेगा।

(7) अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और रद्दकरण की दी गई प्रत्येक सूचना उस सीमा तक जिस तक विधिमान्य है, उस तारीख को जिसको यह लेखाधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है, प्रभावी होगी।

टिप्पण :— इस नियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "व्यक्ति" या "व्यक्तियों" के अंतर्गत कोई कंपनी या संगम या व्यष्टियों का निकाय सम्मिलित होगा चाहे निगमित हो या नहीं और इसके अंतर्गत ऐसी निधि जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता निधि या अन्य दातव्य या अन्य न्यास या निधि में सम्मिलित है, जिनके लिए नामनिर्देशन उक्त निधि या न्यास के सचिव या अन्य कार्यपालक द्वारा संदाय प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से किया जाएगा।

7. अभिदाता का खाता.—प्रत्येक अभिदाता के नाम में एक खाता खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित दर्शित किया जाएगा —

(i) उसके अभिदान;

(ii) नियम 12 में यथाउपबंधित अभिदानों पर ब्याज;

(iii) निधि से अग्रिम और निकासियां।

8. अभिदाय की शर्तें—(1) अभिदाता उस अवधि के सिवाय जब वह निलंबनाधीन हो, मासिक रूप से निधि में अभिदान करेगा :

परन्तु कोई अभिदाता अपने विकल्प पर ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान नहीं करेगा जिसके लिए कोई छुट्टी वेतन नहीं दिया जाता है या छुट्टी वेतन लिया जाता है तो वह अर्द्धवेतन या अर्द्ध औसत वेतन के बराबर या उससे और कम है :

परन्तु यह और कि कोई अभिदाता अपने निलंबन के अधीन अवधि पूरा करने के पश्चात् बहाल होने पर कोई ऐसी रकम जो उस अवधि के लिए संदेय अभिदानों की अधिकतम बकाया रकम से अधिक नहीं है, का संदाय एकमुश्त या किस्तों में करने का विकल्प देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

टिप्पण 1 :— किसी स्थापन में आवधिक पदधारी को निधि में अपने बेरोजगार रहने की अवधि के दौरान अभिदाय करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पण 2 :— सेवा में अकार्य दिन की अवधि के दौरान अभिदाता को अभिदाय करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) अभिदाता उपनियम (1) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट छुट्टी के दौरान अपने अभिदाय न करने के विकल्प की सूचना निम्नलिखित रीति में देगा :—

- (क) यदि वह कोई ऐसा अधिकारी है जो स्वयं ही छुट्टी पर प्रस्थान करने के पश्चात् अपने प्रथम वेतन बिल में अभिदाय के लेखे कोई कटौती किए बिना स्वयं अपने बिलों का आहरण करता है।
- (ख) यदि वह कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो छुट्टी पर प्रस्थान करने से पूर्व अपने विभागाध्यक्ष को लिखित संसूचना द्वारा अपने वेतन बिलों का आहरणकर्ता है।
- (3) सम्यक् और समय से सूचना दिए जाने में असफल रहने को अभिदाय के लिए विकल्प किया गया समझा जाएगा।
- (4) इस नियम के अधीन अभिदाता का सूचित किया गया विकल्प अंतिम होगा।
- (5) ऐसा कोई अभिदाता जिसने नियम 19 के अधीन निधि में अपनी जमाराशि को वापस निकाला है वह उस निधि में ऐसी निकासी के पश्चात् तब तक अभिदाय नहीं करेगा जब तक कि वह ड्यूटी पर वापस न आ जाए।

9. अभिदान की दरें—(1) अभिदाता द्वारा स्वयं ही पूर्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अभिदान की रकम नियत की जाएगी, अर्थात् :—

- (क) यह संपूर्ण रूपों में अभिव्यक्ति की जाएगी;
- (ख) यह कोई भी रकम हो सकेगी जो उसकी परिलब्धियों के छः प्रतिशत से अन्यून और उसकी कुल परिलब्धियों से अनधिक नहीं होगी; परन्तु ऐसे अभिदाता की दशा में जो बोर्ड के अंशदायी भविष्य निधि में पहले से 8-1/3 प्रतिशत की उच्च दर पर अभिदाय कर रहा था, वह कोई रकम हो सकेगी जो उसकी परिलब्धियों से 8-1/3 से अन्यून और उसकी कुल परिलब्धियों से अनधिक होगी;
- (ग) जब कोई कर्मचारी, यथास्थिति न्यूनतम छः प्रतिशत की दर पर या 8-1/3 की दर पर अभिदाय करने का चयन करता है तो निकटतम पचास पैसे तक के अंश को गणना में नहीं लिया जाएगा और पचास पैसे से ऊपर को एक रुपया माना जाएगा।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए किसी अभिदाता की परिलब्धियां निम्नलिखित होगी—

- (क) ऐसे अभिदाता की दशा में जो बोर्ड की सेवा में पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को था वे परिलब्धियां जिनका वह उस तारीख को वह हकदार था :

परन्तु यह कि,—

- (i) यदि अभिदाता उक्त तारीख को छुट्टी पर था और उसने छुट्टी के दौरान अभिदाय करने का विकल्प नहीं दिया था या उक्त तारीख को निलंबनाधीन था, उसकी परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी जिनके लिए वह अपनी ड्यूटी पर वापसी के पश्चात् प्रथम दिन को हकदार था;
- (ii) यदि अभिदाता उक्त तारीख को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उक्त तारीख को छुट्टी पर था और छुट्टी पर बना रहा था तथा ऐसी छुट्टी के दौरान ऐसे अभिदाय के लिए विकल्प किया है तो उसकी परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी जिनके लिए वह तब हकदार होता जब वह भारत में ड्यूटी पर होता।
- (ख) ऐसे किसी अभिदाता की दशा में जो गत वर्ष की 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में नहीं था उसके लिए परिलब्धियां वे होंगी जिनके लिए वह उस तारीख को हकदार था जिसको वह निधि में प्रवेश करता है।
- (3) अभिदाता प्रत्येक वर्ष अपने मासिक अभिदान की रकम का नियतन निम्नलिखित रीति में सूचित करेगा :—
- (क) यदि वह गत वर्ष की 31 मार्च को ड्यूटी पर था तो उस मास के लिए उसके वेतन से इस निमित्त कटौती करके;
- (ख) यदि वह गत वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था तो उसने छुट्टी के दौरान अभिदाय करने का विकल्प नहीं किया था या उस तारीख को निलंबनाधीन था तो उसके ड्यूटी पर वापस आने के पश्चात् उसके प्रथम वेतन बिल से कटौती करने;
- (ग) यदि वह वर्ष के दौरान पहली बार बोर्ड की सेवा में प्रवेश करता है तो उस मास के वेतन बिल से जिसके दौरान वह निधि में प्रवेश करता है इस निमित्त उतनी कटौती करके जितनी वह करवाता है ;
- (घ) यदि वह गत वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था और छुट्टी पर बना रहा था तथा उस छुट्टी के दौरान अभिदाय करने का विकल्प दिया था तो उस मास के उसके वेतन बिल से इस निमित्त की जाने वाली कटौती द्वारा;
- (ङ) यदि वह गत वर्ष की 31 मार्च को विदेश सेवा में था तो उसके द्वारा बोर्ड के खाते में चालू वर्ष के अप्रैल मास के लिए अभिदाय के मद्दे जमा की गई रकम से;
- (4) इस प्रकार नियत की गई अभिदान की रकम,—
- (क) वर्ष के दौरान किसी भी समय कम की जा सकेगी;
- (ख) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाई जा सकेगी; या

(ग) पूर्वोक्तानुसार घटाई और बढ़ाई जा सकेगी :

परन्तु जब अभिदाय की रकम इस प्रकार घटाई जाती है तो वह उपनियम (1) में विहित न्यूनतम से कम नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि कोई अभिदाता किसी कैलेंडर मास के भाग के लिए वेतन के बिना छुट्टी पर है या अर्धवेतन छुट्टी पर है या अर्ध औसत वेतन पर है और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय संदत्त करने का विकल्प किया है तो संदेय अभिदाय की रकम ड्यूटी पर व्यतीत किए गए, जिसके अंतर्गत छुट्टी भी है, यदि कोई हों, उससे या उनसे भिन्न जो ऊपर विनिर्दिष्ट है, की संख्या के अनुपात में होगी।

10. भारत से बाहर विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण—जब कोई अभिदाता भारत से बाहर विदेश सेवा पर स्थानांतरित किया जाता है या प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो वह निधि के नियमों के अधीन वैसे ही रहेगा मानो उसे स्थानांतरित नहीं किया गया हो या प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया हो।

11. अभिदाय की वसूली—(1) बोर्ड को शक्ति होगी कि वह किसी अभिदाता की परिलब्धियों से उससे देय अभिदाय और अग्रिम जो उसे निधि से दिया गया है, पर ब्याज यदि कोई हो, कटौती करे।

(2) जहां किसी अन्य स्रोत से उपलब्धियां आहरित की जाती हैं वहां अभिदाता अपने बकायों को लेखाधिकारी को अग्रेषित करेगा :

परन्तु उस अभिदाता की दशा में जो यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय में प्रतिनियुक्ति पर है, ऐसे निकाय द्वारा अभिदाताओं की वसूली की जाएगी और लेखाधिकारी को अग्रेषित की जाएगी।

(3) यदि कोई अभिदाता उस तारीख से जिसको निधि में उसके सम्मिलित होने की अपेक्षा है, अभिदाय करने में असफल रहता है या नियम 8 में यथा उपबंधित से भिन्न किसी वर्ष के दौरान किसी मास या मासों में व्यतिक्रम करता है, अभिदाय को बकाया के मद्दे निधि में देय संपूर्ण रकम उस पर नियम 12 में उपबंधित दर पर ब्याज सहित तुरंत अभिदाता द्वारा निधि में संदत्त की जाएगी या व्यतिक्रम करने पर लेखाधिकारी के आदेश द्वारा अभिदाता की परिलब्धियों से या अन्यथा कटौती करके वसूली की जानी है, जैसा कि नियम 13 के उपनियम (2) के अधीन अपेक्षित विशेष कारणों से अग्रिम की मंजूरी अनुदत्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशित किए जाए ;

परन्तु ऐसे अभिदाताओं से जिनकी निधियों में निक्षेपों पर कोई ब्याज नहीं है, किसी ब्याज का संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

12. ब्याज,—(1) बोर्ड उपनियम (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अभिदाता के खाते में जमा पर ऐसी दर पर ब्याज का संदाय करेगा जो प्रत्येक वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित परिकलन पद्धति के अनुसार अवधारित की जाए :

परन्तु यदि किसी वर्ष के लिए अवधारित ब्याज दर चार प्रतिशत से कम है तो निधि के सभी अभिदाता उस वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में जिसके लिए पहली बार दर चार प्रतिशत से कम नियत की गई है, चार प्रतिशत पर ब्याज अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसे किसी अभिदाता को भी जो पहले से केन्द्रीय सरकार की अन्य भविष्य निधि में अभिदाय कर रहा था और उसके अभिदान उन पर ब्याज सहित नियम 22 के अधीन उसकी जमा निधि में अंतरित कर दिए गए हैं, चार प्रतिशत का ब्याज अनुज्ञात किया जाएगा यदि वह ऐसी अन्य निधि के नियमों के अधीन ऐसी ब्याज दर उस उपबंध के अधीन जो इन नियम के प्रथम परन्तुक के समान है, प्राप्त कर रहा था।

(2) ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंतिम दिन से निम्नलिखित रीति में जमा किया जाएगा :—

- (i) गत वर्ष के अंतिम दिन किसी अभिदाता की जमा रकम पर चालू वर्ष के दौरान बारह मास में निकाली गई रकम पर ब्याज कम करके ;
- (ii) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई रकम पर ब्याज चालू वर्ष के आरंभ से निकाली गई रकम के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन तक ;
- (iii) ऐसी सभी रकमों पर जो, अभिदाता के खाते में पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन के पश्चात् जमा की गई है, ब्याज निक्षेप की तारीख से चालू वर्ष की समाप्ति तक ;
- (iv) ब्याज की कुल रकम निकटतम संपूर्ण एक रुपए तक पूर्णांकित की जाएगी (पचास पैसे के अगले रुपये के रूप में गणना करके) :

परन्तु जब किसी अभिदाता की जमा राशि में कोई रकम संदेय हो गई है तब उस पर ब्याज इस नियम के अधीन केवल उस अवधि की बाबत यथास्थिति जमा वर्ष के आरंभ से या निक्षेप की तारीख से उस तारीख तक जिसको अभिदाता की जमा रकम पर ब्याज संदेय हो जाता है, जमा की जाएगी।

(3) इस नियम में, परिलब्धियों से वसूली की दशा में निक्षेप द्वारा तारीख उस मास का प्रथम दिन समझी जाएगी जिसमें यह वसूल किया जाता है और अभिदाता द्वारा अग्रेषित किसी रकम की दशा में प्राप्ति के मास का प्रथम दिन समझा जाएगा यदि यह लेखा अधिकारी द्वारा उस मास की पांच दिन से पूर्व यह प्राप्त होता है यदि यह उस मास के पांचवे दिन या उसके पश्चात् प्राप्त होता है तो अगले उत्तरवर्ती मास का प्रथम दिन होगा ;

परन्तु यह कि जहां अभिदाता के वेतन या छुट्टी-वेतन और भत्ते के आहरण में कोई विलंब रहा है और तत्पश्चात् निधि के मद्दे उसके अभिदाय में वसूली में विलंब हुआ है ऐसे अभिदाय पर ब्याज उस मास से संदेय होगी जिसमें अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन उस मास को ध्यान में लाए बिना जिसमें वास्तव में नियमों के अधीन आहरित किया गया था;

परन्तु यह और कि नियम 11 के उपनियम 2 कि परन्तुक के अनुसार अग्रेषित की गई रकम की दशा में निक्षेप की तारीख मास का प्रथम दिन समझा जाएगा यदि यह लेखाधिकारी द्वारा उस मास के 15 तारीख से पूर्व प्राप्त किया जाता है।

परन्तु यह भी कि जहां किसी मास के लिए परिलब्धियां उसी मास के अंतिम दिन आहरित और संवितरित की जाती हैं वहां ब्याज की तारीख अभिदान की वसूली की दशा में उत्तरवर्ती मास का प्रथम दिन समझी जाएगी।

4. नियम 18, नियम 19 या नियम 20 के अधीन संदत्त की जाने वाली रकम के अतिरिक्त उस पर ब्याज उस पश्चातवर्ती मास के अंत तक जिसमें संदाय किया जाता है या उस मास के पश्चात् जिसमें ऐसी रकम संदेय हो जाती है छह मास की समाप्ति तक इनमें से जो अवधि कम हो, उस व्यक्ति को जिसको ऐसी रकम संदत्त की जानी है, संदेय होगी;

परन्तु जहां लेखाधिकारी उस व्यक्ति (या उसके अभिकर्ता) को वह तारीख सूचित करता है जिसको वह नगद में संदाय करने के लिए तैयार है या उस व्यक्ति को संदाय के रूप में चैक भेज दिया है, ब्याज केवल यथास्थिति उसे सूचित की गई तारीख के पश्चातवर्ती मास के अंत तक या चैक भेजने की तारीख तक संदेय होगी;

परन्तु यह और कि जहां कोई अभिदाता केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय या किसी स्वायत्तशासी संगठन जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, में प्रतिनियुक्ति पर है तत्पश्चात् किसी भूतलक्षी तारीख से ऐसे निगमित निकाय या संगठन में आमेलित हो जाता है तो उस अभिदाता की संराशिकृत निधि में देय ब्याज की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आमेलन के समय में जारी किए गए आदेश की तारीख वह तारीख समझी जाएगी, जिसको अभिदाता के निक्षेप में रकम संदेय हो जाती है, तथापि इस शर्त के साथ आमेलन के प्रारम्भ होने की तारीख से और आमेलन के आदेश जारी करने के तारीख तक की अवधि के बीच अभिदान के रूप में वसूल की गयी रकम निधि में इस उपनियम के अधीन ब्याज देने के प्रयोजन के लिए अभिदाय समझी जाएगी।

टिप्पण : छह मास से अधिक की अवधि के लिए निधि अतिशेष पर ब्याज का संदाय अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अपना व्यक्तिगत रूप से यह समाधान होने जाने पर कि इस संदाय में विलम्ब अभिदाता या उस व्यक्ति जिसे ऐसा संदाय किया जाना था नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण हुआ था और ऐसी प्रत्येक दशा में इस मामले में अन्तर्वर्तित प्रशासनिक विलम्ब का पूर्ण रूप से अन्वेषण किया जाएगा और कोई कार्रवाई यदि अपेक्षित हो, की जाएगी।

(5) किसी अभिकर्ता के खाते में ब्याज जमा नहीं की जाएगी यदि वह लेखाधिकारी को यह सूचित करता है कि वह इसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है; किन्तु यदि वह तत्पश्चात् ब्याज मांगता है तो यह उस वर्ष के पहले दिन, जिसमें वह चाहता है, जमा कर दी जाएगी।

(6) उस रकम पर ब्याज जो नियम 11 के उपनियम (3), नियम 18 या नियम 19 के अधीन अभिदाता की निधि में ब्याज में परिवर्तित कर दी गई है ऐसी दरों पर परिगणित की जाएगी जो उस नियम के उपनियम (1) के अधीन बाद में वसूली की जाए और वह ऐसी रीति में होगी, जो इस नियम में वर्णित की जाएगी।

(7) यदि यह पाया जाता है कि अभिदाता ने निधि से आहरण की तारीख को अपने खाते में जमा रकम से अधिक रकम आहरित की है तो अधिक आहरित की गई रकम, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि चाहे अधिक आहरण निधि से अग्रिम या निकासी या अंतिम संदाय के रूप में किया गया है उसके द्वारा उस पर एक मुश्त ब्याज सहित प्रतिसंदत्त की जाएगी या व्यतिक्रम करने पर अभिदाता की परिलब्धियों से एक मुश्त वसूली का आदेश करके वसूल की जाएगी।

(8) यदि वसूल की जाने वाली कुल रकम अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो वसूलियां मासिक किश्तों में उसकी परिलब्धियों के अर्धांश से तब तक की जाएगी जब तक संपूर्ण रकम ब्याज सहित वसूल नहीं हो जाती।

(9) उपनियम (7) के लिए आहरण की गयी अध्यादान रकम पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज की दर उपनियम (1) के अधीन भविष्यनिधि अतिशेष पर सामान्य दर से ढाई प्रतिशत अधिक होगी; और आहरण की गई अध्यादान रकम के समय में वसूल की गई ब्याज बोर्ड के खाते में (भविष्यनिधि से अध्यादान आहरण पर ब्याज) सुभिन्न उपशीर्ष के अधीन जमा की जाएगी।

13. निधि से अग्रिम.—(1) बोर्ड का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी अभिदाता को कोई अग्रिम की रकम जो कुल मिलाकर रुपयों में तीन मास के खर्च से अधिक या निधि में उसकी जमा रकम के आधे से अधिक, जो भी कम हो, से अधिक न हो; निम्नलिखित प्रयोजनों में से एक या अधिक के लिए मंजूर कर सकेगा :—

- (क) बीमारी, परिरोध या अपंगता का खर्च, जिसके अन्तर्गत यथा आवश्यक अभिदाता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति के यात्रा व्यय भी हैं, के संदाय के लिए;
- (ख) उच्चतर शिक्षा जिसके अन्तर्गत जहां आवश्यक हो अभिदाता और कुटुम्ब के सदस्य या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति का यात्रा व्यय भी है के खर्च को निम्नलिखित मामलों में पूरा करने के लिए अर्थात् :—
 - (i) भारत से बाहर शैक्षिक, तकनीकी, वृत्तिक या हाई स्कूल प्रक्रम से ऊपर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए; और
 - (ii) भारत में हाई स्कूल प्रक्रम से ऊपर किसी चिकित्सीय, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञता प्राप्त पाठ्यक्रम के लिए;

परन्तु अध्ययन का पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम न हो;

- (ग) अभिदाता की प्रास्थिति के समुचित मानदंड पर बाध्यताकारी व्ययों, जो प्रथा और रूढ़िजनता के कारण अभिदाता द्वारा सगाई या विवाह या अंत्येष्टि या अन्य समारोह पर उपगत व्यय के संदाय के लिए;
- (घ) अभिदाता या अभिदाता के विरुद्ध या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या उसके ऊपर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए इस मामले में अग्रिम बोर्ड के किसी अन्य आश्रित से उसी प्रयोजन के लिए ग्राही अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध है;

(ड) किसी अभिदाता द्वारा प्रतिरक्षा जहां वह किसी अभिकथित कार्यालयी दुराचार या उसके भाग की बाबत किसी जांच में स्वयं की प्रतिरक्षा के लिए किसी विधि व्यवसाय के खर्च को पूरा करने के लिए के रखे जाने के लिए;

(च) खपत योग्य वस्तुएं जैसे टेलीविजन, वीडियो कैसेट, रिकार्डर, धुलाई मशीन, कुकिंग रेंज, गीजर और कंप्यूटर क्रय करने के लिए।

(2) अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में, किसी भी अभिदाता को किसी अग्रिम के रूप में संदाय की मंजूरी दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि संबद्ध अभिदाता के लिए उपनियम (1) में वर्णित कारणों से भिन्न कारणों के लिए अग्रिम अपेक्षित है।

(3) लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के सिवाय कोई अग्रिम किसी अभिदाता को उपनियम (1) में अधिकथित सीमा से अधिक या किसी पूर्व अग्रिम की अंतिम किस्त का प्रतिदाय होने तक मंजूर नहीं किया जाएगा।

(4) जहां कोई अग्रिम उपनियम (3) के अधीन किसी पूर्व अग्रिम की अंतिम किस्त के प्रतिदाय के पूरा होने से पूर्व मंजूर किया जाता है, वहां वसूल न किए गए किसी अग्रिम के अतिशेष को इस प्रकार मंजूर किए गए अग्रिम में जोड़ा जाएगा और वसूली की किस्तें समेकित रकम के प्रति निर्देश से नियत की जाएंगी।

(5) अग्रिम मंजूर करने के पश्चात उस दशा में जहां अंतिम संदाय के लिए आवेदन नियम 21 के उपनियम (3) के खंड (i) के अधीन लेखाधिकारी को अग्रेषित किया गया था, वहां रकम लेखाधिकारी के किसी प्राधिकार के अधीन आहारणित की जाएगी।

टिप्पण 1.—इस नियम के प्रयोजन के लिए वेतन के अंतर्गत, जहां लागू हों, वहां मंहगाई वेतन सम्मिलित है।

टिप्पण 2.—इस नियम के अधीन अग्रिम मंजूरी के लिए प्राधिकृत किए जाने वाले अधिकारी अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट हैं।

टिप्पण 3.—कोई अभिदाता उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन प्रत्येक छः मास में एक बार अग्रिम लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

14. अग्रिमों की वसूली.—अभिदाता से किसी अग्रिम की वसूली एक समान मासिक किस्तों में उस रीति में की जाएगी, जो मंजूर करने वाला प्राधिकारी निर्देश दें; किन्तु ऐसी संख्या बारह से कम और बारह और चौबीस से अधिक नहीं होगी, जब तक कि अभिदाता ऐसा चयन न करें।

(2) विशेष मामलों में, जहां नियम 13 के उपनियम (3) के अधीन अग्रिम की रकम अभिदाता के तीन मास के वेतन से अधिक हैं, वहां मंजूर करने वाला प्राधिकारी ऐसी रीति में किस्तें नियत कर सकेगा कि, वे चौबीस से अधिक हों किन्तु किसी भी दशा में छत्तीस से अधिक न हों।

(3) कोई अभिदाता अपने विकल्प पर, किस मास में एक से अधिक किस्त का प्रतिदाय कर सकेगा; और प्रत्येक किस्त रूपयों में पूर्णांकित होगी, यदि ऐसी आवश्यक हो ऐसी किस्तों के नियतन को स्वीकार करने के लिए अग्रिम की रकम बढ़ाई या घटाई जा रही हो।

(4) अभिदायों की वसूली के लिए नियम 11 में विहित रीति में वसूली की जाएगी और उस मास का जिसमें अग्रिम आहारणित किया गया था, वेतन जारी किए जाने के एक मास पश्चात् वसूली आरम्भ होगी।

(5) अभिदाता की सहमति के बिना वसूली तब नहीं की जाएगी जब वह जीवन निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा हो या वह किसी ऐसे कैलेंडर मास में, दस या दस से अधिक दिन के लिए छुट्टी पर हों, जिसमें वह यथास्थिति, या तो कोई छुट्टी वेतन नहीं लेता है या अपने आधे वेतन या औसत आधे वेतन के बराबर छुट्टी वेतन लेता है।

(6) मंजूरी प्राधिकारी द्वारा, अभिदाता के लिखित अनुरोध पर अभिदाता को मंजूर किए गए वेतन के अग्रिम की वसूली के दौरान वसूली स्थगित की जा सकेगी।

(7) यदि अभिदाता को एक से अधिक अग्रिम दिए गए हैं तो, वसूली के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक अग्रिम को पृथक समझा जाएगा।

(8) इस नियम के अधीन की गई वसूलियां इस प्रकार जमा की जाएंगी भातों वे निधि में अभिदाता के खाते में जमा की गई हों।

(9) यदि कोई अग्रिम किसी अभिदाता को मंजूर किया गया है उसके द्वारा वह आहारणित किया गया है और प्रतिदाय के पूरा होने से पूर्व अग्रिम को अननुज्ञात किया जाता है तो अभिदाता द्वारा निधि में निकाली गई संपूर्ण रकम या अतिशेष का तुरन्त प्रतिदाय किया जाएगा या व्यतिक्रम करने पर लेखाधिकारी द्वारा आदेश किए जाने पर अभिदाता की परिलब्धियों में से, एकमुश्त या मासिक किस्तों में जो बारह से अधिक नहीं होंगी जैसा कि अग्रिम मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम 13 के उपनियम (3) के अधीन यथापेक्षित विशेष कारणों का उल्लेख करते हुए निर्देशित किया जाए, कटौती वसूल की जा सकेगी :

परन्तु ऐसे अग्रिम के अननुज्ञात किए जाने से पूर्व, अभिदाता को मंजूरी प्राधिकारी को लिखित में और संसूचना प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर यह स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा कि क्यों न प्रतिदाय को प्रवृत्त किया जाए और यदि अभिदाता द्वारा उक्त पंद्रह दिन की अवधि के भीतर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और यदि उसके द्वारा उक्त अवधि के भीतर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, अग्रिम का प्रतिदाय इस उपनियम में विहित रीति में प्रवृत्त किया जाएगा।

15 अग्रिम का गलत उपयोग.—(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी मंजूरी प्राधिकारी के पास इस बात का संदेह करने का कोई कारण है कि नियम 13 के अधीन निधि से आहारणित की गई अग्रिम की रकम का उस प्रयोजन से भिन्न उपयोग किया गया है जिसके लिए धन के आहरण के लिए मंजूरी दी गई थी तो वह अभिदाता को अपने संदेह के कारणों को संसूचित करेगा और उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह संसूचना प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर यह स्पष्टीकरण दें कि क्या अग्रिम का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए धन आहरित करने की मंजूरी दी गई थी।

(2) यदि मंजूरी प्राधिकारी उक्त पन्द्रह दिन के भीतर अभिदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है तो वह अभिदाता को यह निदेश देगा कि वह तुरन्त निधि में प्रशंगत रकम का प्रतिदाय करें या व्यक्तिगत रूप से वह आदेश देगा कि अभिदाता की परिलब्धियों से चाहे वह छुट्टी पर ही क्यों न रहा हो, एकमुश्त रकम की कटौती करके वसूल की जाए।

(3) यदि प्रतिदाय की जाने वाली कुल रकम अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो वसूलियां उसकी परिलब्धियों के अर्धांश से मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक की कुल रकम का उसके द्वारा प्रतिदाय नहीं कर दिया जाता।

टिप्पण : इन नियमों में "परिलब्धियों" में जीवन निर्वाह अनुदान सम्मिलित नहीं है।

16. निधि से निकासी.—(1) इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अध्यक्ष या मंजूरी प्राधिकारी द्वारा निकासियां निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किसी भी समय मंजूर की जा सकेंगी—

(अ) सेवा के पन्द्रह वर्ष पूरा करने के पश्चात् (जिसके अंतर्गत खंडित सेवाकाल, यदि कोई हो भी है) या उसकी सेवानिवृत्ति या अधिवार्षिता की तारीख से दस वर्ष के भीतर जो भी पूर्वतर हों, अभिदाता की विधि में जमा रकम से निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात् :—

(क) उच्चतर शिक्षा का खर्चा पूरा करने के लिए, जिसके अंतर्गत जहां आवश्यक हो, निम्नलिखित मामलों में अभिदाता या अभिदाता के किसी बच्चे का यात्रा व्यय भी है, अर्थात् :—

(i) भारत से बाहर शैक्षिक, तकनीकी, वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम हाई स्कूल प्रक्रम से ऊपर शिक्षा के लिए; और

(ii) भारत में हाई स्कूल के स्तर से ऊपर के चिकित्सा, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञता पाठ्यक्रम के लिए;

(ख) अभिदाता या उसके पुत्रों या पुत्रियों और उस पर वास्तव में आश्रित किसी महिला संबंधी को सगाई या विवाह के संबंध में खर्चों को पूरा करने के लिए;

(ग) रुग्णता जिसके अंतर्गत, जहां आवश्यक हो, अभिदाता के और उसके कुटुम्ब के सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति के यात्रा के संबंध में खर्चों को पूरा करने के लिए;

(घ) उपभोक्ता वस्तुओं जैसे टेलीविजन, वीडियो कैसेट रिकार्डर या वीडियो कैसेट प्लेयर, धुलाई मशीनें, कुकिंग रेंज, गीजर और कंप्यूटर की लागत को पूरा करने के लिए;

(आ) किसी अभिदाता की सेवा के दौरान उसकी निधि में उसके नाम जमा में रकम में से निम्नलिखित प्रयोजनों में से एक या अधिक के लिए, अर्थात् :—

(क) उसके निवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या बना-बनाया फ्लैट अर्जित करने जिसके अंतर्गत किसी प्राधिकरण, राज्य आवासन या किसी गृह निर्माण सोसाइटी द्वारा कोई प्लॉट या फ्लैट के आबंटन मददे कोई संदाय या स्थल की लागत भी है;

(ख) अपने निवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या बना-बनाया फ्लैट अर्जित करने के लिए अभिव्यक्त रूप से लिए गए ऋण मददे बकाया रकम का संदाय करने के लिए;

(ग) अपने निवास के लिए गृह स्थल खरीदने और उस पर मकान बनाने के लिए या इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप से लिए गए ऋण मददे बकाया रकम का प्रतिसंदाय करने के लिए;

(घ) अभिदाता के पहले से ही स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अर्जित किए गए मकान या फ्लैट के पुनर्निर्माण या उसमें कुछ जोड़ने या परिवर्तन करने के लिए;

(ङ) पैतृक गृह या बोर्ड से ली गई सहायता या ऋण से बनाए गए मकान के नवीकरण, उसमें जोड़ने या परिवर्तन करने अथवा उसकी मरम्मत करने के लिए;

(च) खंड (ग) के अधीन क्रय किए गए स्थल पर मकान का संनिर्माण करने के लिए

(इ) अधिवार्षिता पर अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व बारह मास के भीतर निधि में जमा रकम से किसी प्रयोजन को जोड़े बिना।

(ई) अभिदाता द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्व वित्तपोषण और अभिदायी आधार पर ग्रुप इश्योरेंस स्कीम मददे संदेय एक वर्ष के अभिदान के बराबर रकम से किसी वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार।

टिप्पण 1.—(क) ऐसा अभिदाता जिसने स्वयं गृह निर्माण प्रयोजन के लिए अग्रिम के अनुदान लिए शहरी मंत्रालय की स्कीम के अधीन अग्रिम लिया है या जिसे इस संबंध में बोर्ड के किसी अन्य स्रोत से कोई सहायता अनुज्ञात की गई है, उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए खंड (आ) के उपखंड (क), (ग), (घ) और (च) के अधीन अंतिम निकासी के लिए अनुदान हेतु पात्र होगा और पूर्वोक्त स्कीम के अधीन लिए गए किसी ऋण के प्रतिसंदाय के प्रयोजन के लिए नियम 17 के उपनियम (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए पात्र होगा।

(ख) यदि अभिदाता के पास कोई पैतृक मकान है या उसने अपने कर्तव्य के स्थान से भिन्न स्थान पर सरकार से लिए गए ऋण की सहायता से मकान बनाया है तो वह अपने कर्तव्य के स्थान पर गृहस्थल के क्रय के लिए या कोई अन्य मकान बनाने के लिए या बना-बनाया फ्लैट अर्जित करने के लिए खंड (आ) के उपखंड (क), (ग) और (च) के अधीन अंतिम निकासी मंजूर किए जाने का पात्र होगा।

टिप्पण 2.—खंड (आ) के उपखंड (क), (घ), (ङ) या (च) के अधीन निकासी को मंजूरी तभी दी जाएगी जब अभिदाता ने उस क्षेत्र के स्थानीय नगरपालिका निकाय द्वारा जहां उक्त स्थल या मकान स्थित है और ऐसा उन्हीं मामलों में जहां नक्शा वास्तव में अनुमोदित कराया जाता है, सम्यक् रूप से बनाए जाने वाले मकान या उसमें किए जाने वाले परिवर्तन या वृद्धि के लिए नक्शा प्रस्तुत कर दिया गया हो।

टिप्पण 3.—खंड (आ) के उपखंड (ख) के अधीन मंजूर की गई निकासी की रकम आवेदन की तारीख को अतिशेष और उपखंड (क) के अधीन पूर्ववर्ती निकासी की रकम सहित तीन चौथाई से अधिक नहीं होगी जिसमें से पूर्ववर्ती निकासी की रकम घटा दी जाएगी। अनुसरण किया जाने वाला सूत्र है, उस तारीख को अतिशेष धन प्रश्रुत मकान के लिए पूर्ववर्ती निकासी की रकम की तीन चौथाई जिसमें से पूर्ववर्ती निकासी की रकम घटा दी जाएगी।

टिप्पण 4.—खंड (आ) के उपखंड (क) या (घ) के अधीन निकासी वहां भी अनुज्ञात की जाएगी जहां गृह स्थल या गृह पत्नी या पति के नाम में है परन्तु वह पत्नी या पति अभिदाता द्वारा किए गए नाम निर्देशन में भविष्य निधि की रकम प्राप्त करने के लिए प्रथम नामनिर्देशिनी हो।

टिप्पण 5.—(क) इस नियम के अधीन एक ही प्रयोजन के लिए केवल एक ही निकासी अनुज्ञात की जाएगी किन्तु विभिन्न बच्चों के विवाह या शिक्षा या विभिन्न अवसरों पर बीमारी या उस क्षेत्र के जहां उक्त मकान या फ्लैट स्थित है, स्थानीय नगरपालिका निकाय द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित नए नक्शे के अन्तर्गत आने वाले मकान या फ्लैट में वृद्धि या परिवर्तन एक ही प्रयोजन के रूप में नहीं माने जाएंगे;

(ख) बच्चे की शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए निकासी वार्षिक आधार पर तब तक अनुज्ञात की जाएगी जब तक संबद्ध बच्चा तकनीकी या वृत्तिक पाठ्यक्रम को पूरा करता है।

(ग) खंड (आ) के उपखंड (क) या (च) के अधीन उसी मकान को पूरा करने के लिए दूसरी या पश्चात्पूर्वी निकासी टिप्पण 3 के अधीन अधिकथित सीमा तक अनुज्ञात की जाएगी।

टिप्पण 6.—इस नियम के अधीन निकासी की मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि धारा 13 के अधीन किसी अग्रिम को उसी प्रयोजन के लिए और उसी समय मंजूरी दी जा रही हो।

2. जब भी अभिदाता साधारण भविष्य निधि खाते में अपनी जमा रकम के बारे में साधारण भविष्य निधि लेखा के बारे में अंतिम उपलब्ध विवरण के संबंध में पश्चात्पूर्वी अभिदान के साक्ष्य के साथ सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में हो, तब सक्षम प्राधिकारी स्वयं प्रतिदेय किए जाने योग्य अग्रिम की दशा में विहित सीमाओं के भीतर निकासी मंजूर कर सकेगा। ऐसा करने में सक्षम प्राधिकारी उसके द्वारा अभिदाता के पक्ष में पहले मंजूर की गई किसी निकासी या प्रतिदेय अग्रिम को ध्यान में रखेगा।

(3) जहां अभिदाता सक्षम प्राधिकारी को अपनी जमा रकम के बारे में समाधान करने की स्थिति में नहीं है या जहां उस निकासी की ग्राह्यता के बारे में जिसके लिए आवेदन किया गया है, कोई संदेह है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिदाता की जमा रकम को सुनिश्चित करने के लिए लेखाधिकारी को निर्देश किया जा सकेगा जिससे सक्षम प्राधिकारी निकासी की रकम की ग्राह्यता का अवधारण करने में समर्थ हो सके।

(4) निकासी की मंजूरी में प्रमुख रूप से साधारण भविष्य निधि खाता संख्या और लेखा रखने वाले लेखाधिकारी का उल्लेख होना चाहिए और मंजूरी की एक प्रति सदैव उस लेखाधिकारी को पृष्ठांकित की जानी चाहिए। मंजूरी प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि लेखाधिकारी से इस बारे में अभिस्वीकृति अभिप्राप्त कर ली गई है कि निकासी की मंजूरी अभिदाता के खाते लेखा में दर्ज कर दी गई है।

(5) यदि लेखाधिकारी यह रिपोर्ट देता है कि मंजूर की गई निकासी अभिदाता के खाते में जमा रकम से अधिक है या अन्यथा स्वीकार्य नहीं है तो अभिदाता द्वारा निकाली गई राशि तत्काल अभिदाता द्वारा निधि में एकमुश्त में प्रतिसंदत्त की जाएगी और यदि ऐसा प्रतिसंदाय करने में व्यतिक्रम होता है तो मंजूरी प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया जाएगा कि उक्त धनराशि एकमुश्त या ऐसी मासिक किस्तों में जो अध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाएं, उसकी उपलब्धियों से वसूल की जाए।

(6) निकासी का मंजूर हो जाने के पश्चात् रकम उन मामलों में लेखाधिकारी से प्राधिकार पर आहरित की जाएगी जहां अंतिम संदाय के लिए आवेदन नियम 22 के उपनियम (3) के खंड (i) के अधीन लेखाधिकारी को अग्रेषित किया गया था।”;

17. निकासी की शर्तें,— (1) निधि में अभिदाता के नाम जमा राशि में से नियम 16 में विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिए एक बार में निकाली गई राशि सामान्यतया ऐसी राशि के आधे या छह माह के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी :

परन्तु मंजूरी प्राधिकारी निम्नलिखित का यथोचित ध्यान रखते हुए खंड (अ) के अधीन निकासी की दशा में इस सीमा से अधिक निधि में उसके नाम अतिशेष की तीन चौथाई राशि के आहरण की मंजूरी दे सकेगा (i) वह उद्देश्य जिसके लिए निकासी की जा रही है; (ii) अभिदाता की प्रास्थिति ; और (iii) निधि में उसके नाम जमा राशि और नियम 16 के उपनियम (1) के खंड (आ) के अधीन निकासियों की दशा में 90% तक की मंजूरी दे सकेगा :

परन्तु यह और कि किसी भी दशा में नियम 16 के उपनियम (i) के खण्ड (आ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निकासी की अधिकतम रकम गृह निर्माण प्रयोजनों के लिए अग्रिमों के अनुदान हेतु शहरी विकास मंत्रालय की स्कीम के नियम 2(क) और 3(ख) के अधीन समय-समय पर विहित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी;

परन्तु यह भी ऐसे अभिदाता की दशा में जिसने स्वयं गृह निर्माण के प्रयोजनों के लिए अग्रिमों के अनुदान के लिए शहरी विकास मंत्रालय की स्कीम के अधीन कोई अग्रिम लिया है या किसी अन्य सरकारी स्रोत से इस संबंध में कोई सहायता उसे अनुज्ञात की गई है तो, पूर्वोक्त स्कीम के अधीन लिए गए अग्रिम की रकम या किसी अन्य सरकारी स्रोत से ली गई सहायता की रकम सहित इस उपनियम के अधीन निकाली गई धनराशि 75000/- रुपए (पचहत्तर हजार रुपए) या पांच वर्ष के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी;

परन्तु यह और भी कि ऐसे अभिदाता की दशा में जिसने स्वयं गृह निर्माण प्रयोजनों के लिए अग्रिमों के अनुदान के लिए शहरी विकास मंत्रालय की स्कीम के अधीन कोई अग्रिम लिया है या बोर्ड के किसी अन्य स्रोत से इस संबंध में कोई सहायता अनुज्ञात की गई है, पूर्वोक्त स्कीम के अधीन लिए गए अग्रिम की रकम या बोर्ड के किसी अन्य स्रोत से ली गई सहायता सहित इस उपनियम के अधीन निकाली गई धनराशि पूर्वोक्त स्कीम के नियम 2 (क) और 3 (ख) के अधीन समय-समय पर विहित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह भी कि नियम 16(1) (ग) के अधीन अनुज्ञेय निकासी निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम के नब्बे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 1.—नियम 16 के उपनियम (1) के खंड (अ) के उपखंड (ग) के अधीन अभिदाता को निकासी वार्षिक रूप से उस समय तक अनुज्ञात की जा सकेगी जब तक संबंधित अभिदाता का बच्चा उस पाठ्यक्रम को लेता रहे।

टिप्पण 2.—उन दशाओं में जहां अभिदाता को क्रय किए गए किसी स्थल या मकान या फ्लैट या किसी विकास प्राधिकरण या राज्य आवास बोर्ड या गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी के माध्यम से संनिर्मित किसी मकान या फ्लैट के लिए किस्तों का संदाय करना है वहां उसे, जब उससे किसी किस्त का संदाय करने की मांग की जाए, तब-तब उसे निकासी करने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे प्रत्येक संदाय को नियम 17 के उपनियम (1) के प्रयोजनों के पृथक् प्रयोजन के लिए संदाय माना जाएगा।

(2) ऐसा अभिदाता जिसे नियम 16 के अधीन निधि से धन निकालने की अनुमति दी गई है, ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, मंजूरी प्राधिकारी का यह समाधान करेगा कि धन का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह निकाला गया था और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो इस प्रकार निकाली गई संपूर्ण राशि या उतनी राशि जिसका उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया है जिसके लिए वह निकाली गई थी, एकमुश्त और उस पर नियम 12 के अधीन अवधारित दर पर ब्याज के साथ तत्काल निधि में अभिदाता द्वारा प्रतिसंदर्भ की जाएगी और ऐसे संदाय न करने की दशा में मंजूरी प्राधिकारी द्वारा यह आदेश किया गया है कि उक्त धनराशि एकमुश्त या ऐसी मासिक किस्तों में जो अध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाए, उसकी परिलब्धियों से वसूल की जाए :

परन्तु इस उपनियम के अधीन निकासी का प्रतिसंदर्भ किए जाने से पूर्व अभिदाता को संसूचना की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर लिखित में इस बारे में स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा कि क्यों न प्रतिसंदर्भ प्रवृत्त किया जाए और यदि मंजूरी प्राधिकारी का स्पष्टीकरण से समाधान नहीं होता है या उक्त पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अभिदाता द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो मंजूरी प्राधिकारी इस उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति से प्रतिसंदर्भ प्रवृत्त कराएगा।

(3) (क) ऐसे अभिदाता को जिसे निधि में उसके नाम जमा रकम में से धन निकालने के लिए नियम 16 के उपनियम (1) के खंड (आ) के उपखंड (क), उपखंड (ख) या उपखंड (ग) के अधीन अनुमति दी गई है, इस प्रकार निकाले गए धन से बनाए गए मकान या विक्रय, बंधक (बोर्ड को बंधक से भिन्न), दान, विनियम या अन्य रूप में अर्जित मकान अथवा क्रय किए गए गृह स्थल से अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना बेदखल नहीं किया जाएगा :

परन्तु ऐसी अनुमति—

- (i) किसी ऐसे मकान या गृह स्थल के लिए जो तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर दिया जा रहा हो, आवश्यक नहीं होगी, या
- (ii) आवासन बोर्ड, राष्ट्रीयकरणकृत बैंक या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन जीवन बीमा निगम के पक्ष में बंधक किया जा रहा हो, जिसने नए मकान के निर्माण के लिए या विद्यमान मकान में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए ऋण दिया है;

(ख) अभिदाता प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक इस बारे में घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उक्त मकान या गृह स्थल उसके कब्जे में बना रहा है या बंधक रहा है या पूर्वोक्त रूप में अंतरित किया गया है या उसे किराए पर दिया गया है और यदि अपेक्षित हो तो मंजूरी प्राधिकारी के समक्ष उस तारीख को या उससे पूर्व जो उस प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए मूल विक्रय, बंधक या पट्टा विलेख तथा वे दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिन पर उक्त संपत्ति पर उसका हक आधारित है;

(ग) यदि उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व किसी समय अभिदाता उक्त गृह या गृह स्थल का कब्जा अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना छोड़ देता है तो वह तत्काल उसके द्वारा इस प्रकार निकाली गई धनराशि का एकमुश्त प्रतिसंदर्भ निधि में करेगा और ऐसे प्रतिसंदर्भ के व्यतिक्रम में, मंजूरी प्राधिकारी, उस बारे में अभिदाता को अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उक्त धनराशि को अभिदाता की परिलब्धियों से या तो एकमुश्त या उतनी मासिक किस्तों में जो उसके द्वारा अवधारित की जाए, वसूल कराएगा।

टिप्पण—ऐसा अभिदाता जिसने बोर्ड से ऋण लिया है और उसके बदले बोर्ड को उक्त मकान या गृह स्थल को बंधक रख दिया है, उससे निम्नलिखित आशय की घोषणा प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, अर्थात् :—

“मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि गृह या गृह स्थल जिसके निर्माण के लिए या जिसके अर्जन के लिए मैंने भविष्य निधि से अंतिम निकासी की है, मेरे कब्जे में रहा है किंतु बोर्ड को बंधक रखा है।”

18. अग्रिम का निकासी में संपरिवर्तन, — ऐसा अभिदाता जिसने नियम 16 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए नियम 13 के अधीन पहले ही अग्रिम का आहरण कर लिया है या भविष्य में कर सकता है, वह अपने विवेक पर मंजूरी प्राधिकारी के माध्यम से लेखाधिकारी को संबोधित लिखित अनुरोध द्वारा नियम 16 और 17 में अधिकथित शर्तों को पूरा करके बकाया राशि को अंतिम निकासी में बदल सकेगा।

टिप्पण 1.—लेखाधिकारी वेतन बिलों से वसूलियां रोकने के लिए कार्यालयाध्यक्ष से कह सकेगा जब ऐसे संपरिवर्तन के लिए आवेदन उस प्राधिकारी द्वारा लेखाधिकारी को अग्रेषित किया जाता है।

टिप्पण 2.—नियम 17 के उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन के समय अभिदाता के खाते में उसके नाम जमा रकम पर ब्याज सहित अभिदाय की रकम और अग्रिम की शेष रकम को अतिशेष के रूप में लिया जाएगा; और प्रत्येक निकासी को पृथक् निकासी के रूप में माना जाएगा और एक से अधिक संपरिवर्तनों की दशा में यही सिद्धांत लागू होगा।

1179 45/2005-5

19. निधि में संचित राशि की अंतिम निकासी— जब कोई अभिदाता सेवा छोड़ता है तब निधि में उसके नाम जमा रकम उसे संदेय हो जाएगी:

परन्तु ऐसा अभिदाता जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो तथा बाद में बहाल कर दिया गया हो, तो वह यदि बोर्ड द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो तो नियम 19 के परन्तुक में उपबन्धित रीति से नियम 12 में उपबन्धित दर पर ब्याज के साथ उस राशि को वापस करेगा जो इस नियम का अनुसरण करते हुए उसे निधि से दी गई थी। इस प्रकार वापस की गई रकम निधि में उसके खाते में जमा की जाएगी।

स्पष्टीकरण 1.— ऐसे अभिदाता से भिन्न जिसे संविदा पर नियुक्त किया गया है या जो सेवानिवृत्त हो गया है और जिसे बाद में सेवा भंग या बिना सेवा भंग मानकर पुनर्नियुक्त कर लिया गया है, अभिदाता को तब सेवा छोड़ा हुआ नहीं माना जाएगा जब उसका स्थानांतरण सेवा में बिना किसी भंग के नए पद पर राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में हो जाता है (जिसमें वह दूसरे भविष्य निधि नियमों से शासित होता है) तथा उसके पूर्व पद से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता है। ऐसे मामले में, उसके अभिदान ब्याज सहित निम्नलिखित में अंतरित कर दिए जाएंगे—

(क) यदि नया पद केन्द्रीय सरकार के दूसरे विभाग में है तो, दूसरी निधि के नियमों के अनुसार उस निधि के उसके खाते में ; या

(ख) संबद्ध राज्य सरकार के अधीन नए खाते में, यदि नया पद राज्य सरकार के अधीन हो और राज्य सरकार की साधारण या विशेष आदेश द्वारा इसके से अभिदाय और ब्याज के ऐसे अन्तरण की सहमति देती है।

टिप्पण—स्थानांतरण में अध्यक्ष की उचित अनुमति से बिना सेवा भंग के केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य विभाग में नियुक्ति पाने के लिए सेवा से त्यागपत्र के मामले भी सम्मिलित होंगे :

परन्तु सेवा भंग के मामलों में, यह भिन्न स्थान पर स्थानांतरण होने पर कार्यग्रहण करने के लिए अनुज्ञात समय तक सीमित होगा।

स्पष्टीकरण 2.—जब ऐसे अभिदाता से भिन्न जो संविदा पर नियुक्त किया गया है या जो सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है और बाद में पुनः नियोजित किया जाता है, कोई अभिदाता सेवा में भंग के बिना सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय में या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी संगठन में अंतरित हो जाता है तो अभिदान की राशि और उस पर ब्याज का संदाय उसको नहीं किया जाएगा किन्तु उसका अंतरण उस निकाय की सहमति से उस निकाय के अधीन उसके नए भविष्य निधि खाते में कर दिया जाएगा।

टिप्पण : स्थानांतरण में सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी संगठन में नियुक्ति पाने के उद्देश्य से बोर्ड की पूर्व अनुमति के, बिना सेवाभंग के सेवा से त्यागपत्र के मामले भी सम्मिलित होंगे :

परन्तु नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए गए समय को सेवा-भंग नहीं माना जाएगा यदि वह एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण के मामले में बोर्ड के कर्मचारी को स्वीकार्य कार्य ग्रहण समय से अधिक न हो :

परन्तु यह और कि ऐसे अभिदाता के जो लोक उद्यम में सेवा के लिए अपना विकल्प देता है, अभिदान की रकम तथा उस पर ब्याज,—

(i) यदि वह ऐसी इच्छा व्यक्त करता है तो, उद्यम के अधीन उसकी भविष्य निधि खाते में अंतरित की जा सकेगी, यदि संबद्ध उद्यम भी ऐसे अन्तरण के लिए सहमत होता है;

(ii) यदि अभिदाता अंतरण की इच्छा व्यक्त नहीं करता है या संबद्ध उद्यम कोई भविष्य निधि नहीं संचालित करता है तो पूर्वोक्त रकम अभिदाता को वापस कर दी जाएगी।

20. अभिदाता की सेवानिवृत्ति, —जब अभिदाता—

(क) सेवानिवृत्ति, पूर्व छुट्टी पर चला गया हो, या

(ख) उसे छुट्टी पर रहते हुए सेवानिवृत्ति की अनुमति मिल गई हो या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी ने उसे आगे सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया हो, तो निधि में उसके नाम जमा राशि, उसके द्वारा इस निमित्त लेखाधिकारी को आवेदन करने पर अभिदाता को देय हो जाती है:

परन्तु यह कि अभिदाता यदि छुट्टी पर वापस आ जाता है, यदि बोर्ड द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो तो, इस नियम का अनुसरण करते हुए उसे निधि से उसे दी गई संपूर्ण या आंशिक राशि, नियम 12 में उपबन्धित दर पर ब्याज के साथ नकद या प्रतिभूतियों के रूप में या आंशिक रूप से प्रतिभूतियों में या आंशिक रूप से नकद, किस्तों में या अन्यथा अपनी परिलब्धियों से वसूली द्वारा या अन्यथा अपने खाते में जमा करने के लिए निधि में वापस करेगा, जैसा अग्रिम की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्देश दे, जिसके लिए नियम 13 के उपनियम (3) के अंतर्गत विशेष कारणों की आवश्यकता होती है।

21. अभिदाता की मृत्यु पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया—अभिदाता के नाम जमाराशि के देय होने से पूर्व या जहां राशि देय हो गई है, उसका संदाय किए जाने से पूर्व, अभिदाता की मृत्यु होने पर :

(i) जब अभिदाता कोई कुटुम्ब छोड़ता है—

(क) यदि नियम 6 या इससे पूर्व प्रभावी संगत नियम के उपबन्धों के अनुरूप अभिदाता द्वारा अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन जारी रहता है तो निधि में उसके नाम जमा राशि या उसका भाग जिससे नामनिर्देशन से संबंधित है, नामनिर्देशन में निर्दिष्ट अनुपात में नामनिर्देशिनी या नामनिर्देशितियों को संदेय हो जाएगा;

(ख) यदि अभिदाता के कुटुम्ब के किसी सदस्य या सदस्यों के नाम इस प्रकार का कोई नामनिर्देशन नहीं है या इस प्रकार का नामनिर्देशन निधि में जमा राशि के केवल एक भाग से संबंधित है तो, यथास्थिति नामनिर्देशन से असंबद्ध संपूर्ण राशि या उसका भाग, उसके

कुटुम्ब के किसी सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम आशयित किसी नामनिर्देशन के होते हुए भी समान हिस्सों में उसके कुटुम्ब के सदस्यों को देय हो जाएगा:

परन्तु निम्नलिखित में से किसी को कोई अंश संदेय नहीं होगा :—

- (i) ऐसे पुत्र जो वयस्क हो गए हैं;
- (ii) मृत वयस्क पुत्र के पुत्र;
- (iii) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं;
- (iv) मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं;

खंड (i), (ii) और (iii), (iv) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न यदि कुटुम्ब का कोई सदस्य हो;

परन्तु यह भी कि मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और बच्चा या बच्चे केवल उस भाग का समान भाग पाएंगे जो उस पुत्र को मिलता यदि वह अभिदाता के बाद जीवित रहता तथा उसे प्रथम परन्तुक के खंड (i) के उपबन्धों से छूट प्राप्त होती;

(2) जब अभिदाता कोई कुटुम्ब नहीं छोड़ता है यदि नियम 6 या इससे पूर्व प्रभावी संगत नियम के प्रावधानों के अनुरूप अभिदाता द्वारा अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन जारी रहता है, तो निधि में उसके नाम जमा राशि या उसका भाग जिससे नामनिर्देशन संबंधित है, नामनिर्देशन में निर्दिष्ट अनुपात में नामनिर्देशिनी या नामनिर्देशितियों को संदेय हो जाएगा।

22. निधि में जमा राशि के संदाय की रीति—(1) जब निधि में अभिदाता के नाम जमा राशि देय हो जाती है तो उपनियम (3) में उपबन्धित के अनुसार इस निमित्त लेखाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह लिखित आवेदन प्राप्त होने पर संदाय करे।

(2) यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन कोई रकम या पालिसी संदत्त, समनुदेशित या पुनः समनुदेशित या परिदत्त की जानी है यदि वह पागल हो, जिसकी संपत्ति के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अधीन इस निमित्त किसी प्रबन्धक की नियुक्ति की गई है तो ऐसा संदाय या पुनः समनुदेशन या परिदान ऐसे व्यक्ति को किया जाएगा न कि पागल व्यक्ति को :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति को प्रबन्धक नियुक्त नहीं किया गया है और वह व्यक्ति जिसको रकम संदेय है, मजिस्ट्रेट द्वारा पागल होना प्रमाणित कर दिया गया है को संदाय भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की धारा 95 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार कलक्टर के आदेश के अधीन ऐसे पागलपन के भारसाधक व्यक्ति को किया जाएगा और लेखाधिकारी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उस पागल व्यक्ति का भारसाधन है, ऐसी रकम का संदाय करेगा जिसे वह ठीक समझे और अधिशेष, यदि कोई हो या उसका ऐसा कोई भाग जिसे वह ठीक समझे, ऐसे पागल व्यक्ति के कुटुम्ब के सदस्यों के भरणपोषण के लिए संदत्त किया जाएगा, जो उसके ऊपर भरणपोषण के लिए आश्रित है।

(3) निकाली गई रकम का संदाय केवल भारत में किया जाएगा और वह व्यक्ति जिसको रकम संदेय है, भारत में संदाय प्राप्त करने के लिए उसकी स्वयं की व्यवस्था करेगा।

(4) किसी अभिदाता द्वारा संदाय का दावा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात् :—

(i) कार्यालय अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष लेखाधिकारी को सेवानिवृत्त या सेवा छोड़ने वाले अभिदाता के ब्यौरे उन अग्रिमों के विरुद्ध प्रवृत्त वसूलियां जो अभी भी चालू हैं और किस्तों की संख्या, जिनकी वसूली की जानी है, निकासियां, यदि कोई हों, जो अभिदाता द्वारा किसी निकासी की अंतिम किस्त की अवधि पूरा होने के पश्चात् अभिदाता के खाते से की गई हो, को उपदर्शित करते हुए, यदि कोई हो, अग्रेषित करेगा;

(ii) लेखाधिकारी खाता लेखा से सत्यापन करने के पश्चात् अभिदाता को संदेय रकम के लिए उसकी अधिवर्षिता की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व किंतु अधिवर्षिता की तारीख को संदेय एक प्राधिकार जारी करेगा;

(iii) खंड (iii) में वर्णित प्राधिकार में संदाय की पहली किस्त और संदाय के लिए दूसरा प्राधिकार सम्मिलित होगा, जो अधिवर्षिता के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र जारी किया जाएगा जो अभिदाता द्वारा खंड (ii) के अधीन कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित ब्यौरों में वर्णित रकम के परिणामस्वरूप अभिदाता द्वारा किए गए अभिदान से संबंधित होगा और उस अग्रिम के विरुद्ध प्रतिदाय की किस्तें जो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में चालू थी, भी सम्मिलित होंगी;

(iv) लेखाधिकारी को अंतिम संदाय के लिए खंड (ii) में निर्दिष्ट ब्यौरे अग्रेषित करने के पश्चात् अग्रिम या निकासी मंजूर की जा सकेगी किंतु अग्रिम या निकासी की रकम संबद्ध लेखाधिकारी से किसी प्राधिकार पर आहरित की जाएगी, जो उसके द्वारा मंजूरी प्राधिकारी की औपचारिक मंजूरी प्राप्त होने पर इसकी व्यवस्था करेगा।

टिप्पण—जब अभिदाता के नाम जमा रकम नियम 18, नियम 19 या नियम 20 के अधीन संदेय हो गई हों तब लेखाधिकारी उपनियम (3) में उपदर्शित रीति में रकम का तुरंत संदाय प्राधिकृत करेगा।

23. सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय सेवा से किसी व्यक्ति की बोर्ड की सेवा में अंतरण के संबंध में प्रक्रिया—यदि निधि के लाभ के लिए बोर्ड का कर्मचारी पहले केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन निगमित निकाय या राज्य सरकार या

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संगठन की भविष्य निधि का अभिदाता था तो उसके जमा खाते में अभिदान की रकम उस पर ब्याज सहित अन्य निधि में अंतरण की तारीख को उसकी निधि के जमा खाते में अंतरित हो जाएगी :

परन्तु जहां अभिदाता किसी राज्य सरकार की गैर अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान कर रहा था, वहां उस सरकार की सहमति अभिप्राय की जाएगी।

24. व्यक्तिगत मामलों में नियम के उपबंधों का शिथिलीकरण—(1) जब बोर्ड का यह समाधान हो गया है कि इनमें से किसी नियम को लागू करने से अभिदाता को अनावश्यक कठिनाई होती है या होने की संभावना है तो बोर्ड, इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभिदाता के मामले में ऐसी रीति से व्यवहार करेगा, जो उसे उचित और न्यायसंगत लगे।

25. अभिदाता को परिदान किए जाने वाला वार्षिक लेखा विवरण—(1) यथाशक्य शीघ्र प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च के पश्चात् लेखाधिकारी प्रत्येक अभिदाता को वर्ष की एक अप्रैल को अतिशेष दर्शित करते हुए वर्ष के दौरान जमा की गई या नामे डाली गई कुल रकम वर्ष की 31 मार्च तक जमा की गई ब्याज की कुल रकम और उस तारीख को अंतशेष दर्शित करते हुए उसका एक लेखा विवरण भेजेगा और लेखा विवरण के साथ एक जांच संलग्न करेगा कि क्या अभिदाता,—

(क) नियम 6 के अधीन किए गए किसी नामनिर्देशन में कोई परिवर्तन करना चाहता है;

(ख) उन मामलों में, जहां अभिदाता ने नियम 6 के उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन अपने कुटुंब के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामनिर्देशन नहीं किया हो, क्या उसका अपना कोई कुटुंब है;

(2) अभिदाता को स्वयं वार्षिक विवरण की शुद्धता के संबंध में स्वयं का समाधान कर लेना चाहिए और चुट्टि हो तो उसे विवरण प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर लेखाधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

(3) लेखाधिकारी यदि अभिदाता द्वारा अपेक्षित हो तो वर्ष में एक बार किंतु एक बार से अधिक, अभिदाता को उसकी निधि में जमा रकम के बारे में उस मास के अंत में जिसको उसका लेखा लिखा गया है, सूचित करेगा।

26. अभिदान के संदाय के समय लेखा संख्यांक का उद्धृत किया जाना—कोई अभिदाता भारत में परिलब्धियों से कटौती द्वारा या नकद में अभिदान का संदाय करते समय लेखाधिकारी द्वारा उसे संसूचित की गई निधि की अपनी लेखा संख्या उद्धृत करेगा; और लेखाधिकारी द्वारा संख्या में कोई परिवर्तन तदनुसार अभिदाता को संसूचित किया जाएगा।

27. लेखाओं का रखा जाना—(1) इन नियमों के अधीन निधि में और निधि से संदत्त सभी रकमें बोर्ड की लेखा बहियों में "काफी बोर्ड साधारण भविष्य निधि लेखा" नामक खाते में हिसाब में ली जाएगी।

(2) ऐसे लेखाओं की काफी अधिनियम की धारा 45(3) के अधीन नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक परीक्षा और लेखा परीक्षा की जाएगी।

(3) निधि की अभिरक्षा और संवितरण काफी अधिनियम, 1955 के नियम 35 ठीक उसी रीति में विनियमित किया जाएगा जैसा कि बोर्ड की निधियों को विनियमित किया जाता है।

(4) निधि के सभी व्यय यथासंभव निधि की आय से पूरे किए जाएंगे :

परन्तु घाटा साधारण निधि से पूरा किया जाएगा यदि आय सभी व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

28. निधि का परिसमापन—(1) निधि का परिसमापन किया जाएगा, यदि—

(क) बोर्ड का विघटन अधिनियम की धारा 10 के अधीन अधिसूचना द्वारा किया जाना है; या

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बोर्ड के संकल्प द्वारा किया जाना है।

(2) निधि के परिसमापन पर, आस्तियों की वसूली की जाएगी और अभिदाताओं के बीच उनके खाते के अनुसार संवितरित की जाएगी।

29. निरसन और व्यावृत्ति—(1) काफी बोर्ड साधारण भविष्य निधि नियम, 1965 निरसित किया जाता है :

परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा—

(क) उक्त नियमों का पहले प्रवर्तन या सम्यक् रूप से उनमें की गई कोई बात या किसी का व्यथित होना; या

(ख) उक्त नियमों के अधीन किसी अधिकार, बाध्यता या दायित्व का अर्जित, उद्भूत या उपगत होना; या

(ग) अग्रिम के किसी दोषपूर्ण उपयोग की बाबत कोई वसूली।

30. निर्वचन—इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो, इन्हें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

[सं. 9/3/99-प्लॉट (बी)]

ए. सेनगुप्त, अपर सचिव

काफी बोर्ड साधारण भविष्य निधि, 2004

प्रथम अनुसूची

(नियम 6 का उपनियम 3 देखें)

अभिदाता का नाम : श्री/श्रीमती..... जमाकर्ता का खाता सं.
नामनिर्देशन रजिस्टर पन्ना सं.

अभिदाता का नामनिर्देशन

I. जब अभिदाता का परिवार हो तथा वह उसमें से एक सदस्य को नामित करने का इच्छुक हो।

मैं, नीचे वर्णित व्यक्ति को, जो, काफी बोर्ड साधारण भविष्य निधि नियम, 2004 के नियम 2 में दी गई परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार का सदस्य है, निधि में मेरे नाम जमा राशि को, उसके देय होने या देय होने पर भुगतान न होने से पूर्व मेरी मृत्यु होने की दशा में प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हूँ :—

1. अभिदाता की मृत्यु की दशा में नामनिर्देशित का नाम और पता
2. अभिदाता से संबंध
3. आयु
4. यदि नामनिर्देशित की मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाती है तो उस व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम, पता तथा संबंध जिन्हें नामनिर्देशन के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे।

तारीख.....दिन.....20.....स्थान.....

अभिदाता के हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

पता.....

पते सहित दो साक्षियों के हस्ताक्षर :

(1)

(2)

विशेष ध्यान दें—अभिदाता को अपनी अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान में रेखा खींच देनी चाहिए जिससे उसके हस्ताक्षर करने के बाद इसमें कोई नाम सम्मिलित न किया जा सके। स्तंभ 4 को भरा जाना चाहिए जिससे किसी भी समय निधि में अभिदाता के नाम जमा संपूर्ण राशि को सम्मिलित किया जा सके।

अभिदाता का नाम : श्री/श्रीमती..... जमाकर्ता का खाता सं.
नामनिर्देशन रजिस्टर पन्ना सं.

अभिदाता का नामनिर्देशन

II. जब अभिदाता का परिवार हो और वह उसके एक से अधिक सदस्य को नामित करना चाहता हो।

मैं, नीचे वर्णित व्यक्तियों को, जो, काफी बोर्ड साधारण भविष्य निधि नियम, 2004 के नियम 2 में दी गई परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार का सदस्य है, निधि में मेरे नाम जमा राशि को, उसके देय होने या देय होने पर भुगतान न होने से पूर्व मेरी मृत्यु होने की दशा में प्राप्त करने के लिए नामित करता हूँ तथा यह निर्देश देता हूँ कि उक्त राशि कथित व्यक्तियों के बीच उनके नामों के सामने दर्शाई गई रीति से वितरित की जाएगी :—

अभिदाता की मृत्यु होने की दशा में नामनिर्देशित का नाम और पता	अभिदाता से संबंध	आयु	संराशिकृत राशि से प्रत्येक को दी जाने वाली राशि का हिस्सा
(1)	(2)	(3)	(4)

5. वे आकस्मिकताएं जिनके घटित होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।

1179 97.2005-6

6. यदि नामनिर्देशिनी की मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाती है तो उस व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम, पता तथा संबंध जिन्हें नामनिर्देशन के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे।

तारीख.....दिन.....20.....स्थान.....
 अभिदाता के हस्ताक्षर.....
 पदनाम.....
 पता.....

पते सहित दो साक्षियों के हस्ताक्षर :

(1)

(2)

विशेष ध्यान दें—अभिदाता को अपनी अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान में रेखा खींच देनी चाहिए जिससे उसके हस्ताक्षर करने के बाद इसमें कोई नाम सम्मिलित न किया जा सके। स्तंभ 4 को भरा जाना चाहिए जिससे किसी भी समय निधि में अभिदाता के नाम जमा संपूर्ण राशि को सम्मिलित किया जा सके।

अभिदाता का नाम : श्री/श्रीमती..... जमाकर्ता का खाता सं.
 नामनिर्देशन रजिस्टर पन्ना सं.

अभिदाता का नामनिर्देशन

III. जब अभिदाता का परिवार नहीं हो तथा वह एक सदस्य को नामित करना चाहता हो।

मेरा, काफी बोर्ड साधारण भविष्य निधि नियम, 2004 के नियम 2 में दी गई परिभाषा के अनुसार कोई परिवार नहीं है, मैं निम्नलिखित व्यक्ति को निधि में मेरे नाम जमा राशि को, उसके देय होने या देय होने पर भुगतान न होने से पूर्व मेरी मृत्यु होने की दशा में प्राप्त करने के लिए नामित करता हूँ :—

1. नामनिर्देशिनी का नाम और पता

2. अभिदाता से संबंध

3. आयु**

4. वे आकस्मिकताएं जिनके घटित होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।

5. यदि नामनिर्देशिनी की मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाती है तो उस व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम, पता तथा संबंध जिन्हें नामनिर्देशन के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे।

तारीख.....दिन.....20.....स्थान.....
 अभिदाता के हस्ताक्षर.....
 पदनाम.....
 पता.....

पते सहित दो साक्षियों के हस्ताक्षर :

(1)

(2)

टिप्पण—जहां किसी अभिदाता का कोई कुटुम्ब नहीं है, वह स्तंभ में विनिर्दिष्ट करेगा कि बाद में उसके कुटुम्ब अर्जित होने की दशा में नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।

विशेष ध्यान दें—अभिदाता को अपनी अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान में रेखा खींच देनी चाहिए जिससे उसके हस्ताक्षर करने के बाद इसमें कोई नाम सम्मिलित न किया जा सके। स्तंभ 4 को भरा जाना चाहिए जिससे किसी भी समय निधि में अभिदाता के नाम जमा संपूर्ण राशि को सम्मिलित किया जा सके।

अभिदाता का नाम : श्री/श्रीमती..... जमाकर्ता का खाता सं.
 नामनिर्देशन रजिस्टर पन्ना सं.

अभिदाता का नामनिर्देशन

IV. जब अभिदाता का परिवार न हो तथा वह एक से अधिक सदस्यों को नामित करना चाहता हो।

मैं, जिसका काफी बोर्ड साधारण भविष्य निधि नियम, 2004 के नियम 2 में दी गई परिभाषा के अनुसार कोई परिवार नहीं है, निम्नलिखित व्यक्ति को निधि में मेरे नाम जमा राशि को, उसके देय होने या देय होने पर भुगतान न होने से पूर्व मेरी मृत्यु होने की दशा में प्राप्त करने के लिए नामित करता हूँ तथा यह निर्देश देता हूँ कि उक्त राशि कथित व्यक्तियों के बीच उनके नामों के सामने दर्शाई गई रीति से वितरित की जाएगी :—

1. अभिदाता की मृत्यु होने की दशा में नामनिर्देशिनी का नाम और पता
2. अभिदाता से संबंध
3. आयु
4. *जमा राशि से प्रत्येक को दी जाने वाली राशि का अंश
5. **वे आकस्मिकताएं जिनके घटित होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।
6. यदि नामनिर्देशिनी की मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाती है तो उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का नाम, पता तथा संबंध जिन्हें नामनिर्देशन के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे।

तारीख.....दिन.....20.....स्थान.....

अभिदाता के हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

पता.....

पते सहित दो साक्षियों के हस्ताक्षर :

(1)

(2)

विशेष ध्यान दें—अभिदाता को अपनी अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान में रेखा खींच देनी चाहिए जिससे उसके हस्ताक्षर करने के बाद इसमें कोई नाम सम्मिलित न किया जा सके। स्तंभ 4 को भरा जाना चाहिए जिससे किसी भी समय निधि में अभिदाता के नाम जमा संपूर्ण राशि को सम्मिलित किया जा सके। जहां किसी अभिदाता का कोई कुटुम्ब नहीं है, वह इस स्तंभ में यह विनिर्दिष्ट करेगा कि बाद में उसका कुटुम्ब अर्जित होने की दशा में नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।

काफी बोर्ड साधारण भविष्य निधि, नियम, 2004**द्वितीय अनुसूची**

(नियम 13 का टिप्पण 2 देखें)

अस्थाई अग्रिमों की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी

अध्यक्ष, काफी बोर्ड साधारण भविष्य निधि नियम, 2004 के नियम 13 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अधीन काम करने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अग्रिम मंजूर करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन करता है, जिसके लिए उपनियम (2) के अधीन विशेष कारणों की अपेक्षा नहीं की गई है।

1. सचिव
2. वित्त निदेशक
3. संवर्द्धन निदेशक
4. अनुसंधान निदेशक
5. लेखाधिकारी

6. द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी जिन्हें अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण होने पर यात्रा भत्ता अग्रिम स्वीकार करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों और नियम 13 के उपनियम (2) के अधीन विशेष कारणों के लिए अग्रिम केवल अध्यक्ष द्वारा मंजूर किए जाएंगे।

अध्यक्ष

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

New Delhi, the 15th April, 2005

G.S.R. 132.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942) the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short Title and Commencement — (1) These rules may be called the Coffee Board General Provident Fund Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition—(1) In these Rules, unless the context otherwise requires.—

- (a) "Act" means the Coffee Act, 1942 (7 of 1942);
- (b) "Accounts Officer" means the Accounts Officer of the Board;
- (c) "Board" means the Coffee Board constituted under the Act;
- (d) "Chairman" means the Chairman of the Board;
- (e) "Fund" means the General Provident Fund constituted and established by the Board;
- (f) "Employee" means a salaried officer or employee of the Board other than a person in the service of the Central or the State Government whose services have been lent or transferred to the Board;
- (g) "Emoluments" means pay, leave salary, or subsistence grant as defined in the Fundamental Rules and includes dearness pay appropriate to pay, leave salary or subsistence grant, if admissible, and any remuneration of the nature of pay received in respect of foreign service;
- (h) "Family" means—

- (i) In the case of a male subscriber, the wife or wives, parents, children, minor brother, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grandparent:

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community, to which she belongs to be entitled to maintenance, she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently intimates, in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be so regarded;

- (ii) in the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow

and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grandparent:

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

NOTE : 'Child' means a legitimate child and includes an adopted child where adoption is recognized by the personal law governing the subscriber or a ward under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), who lives with the employee and is treated as a member of the family and to whom the employee has through a special will, given the same status as that of natural born child;

- (i) "Leave" means any leave recognized by Fundamental Rules or the Civil Service Regulations or the Revised Rules 1933;

- (j) "Year" means a financial year;

(2) Any other expression used in these rules which is defined either in the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), or in the Fundamental Rules is used in the sense there in defined.

3. Constitution of the Fund—(1) The fund shall be maintained in rupees.

(2) All sums paid into the Fund under these rules shall be credited in the books of Board to an account named "The General Provident Fund".

(3) Sums of which payment has not been taken within six months after they become payable under these rules shall be transferred to "Deposits" at the end of the year and treated under the ordinary rules relating to deposits.

4. Management of the Fund—(1) The Fund shall vest in the Board and be managed by the Executive Committee or by the Chairman to such extent as may be specified by the Executive Committee on behalf of the Board.

(2) The decision of the Board regarding the management of Fund shall be binding upon the members.

5. Conditions of Eligibility—(1) All temporary employees of the Board after a continuous service of one year, all re-employed pensioners (other than those eligible for admission to the Contributory Provident Fund) and all permanent employees shall subscribe to the Fund.

(2) Re-employed pensioners may, at their option, subscribe to the General Provident Fund.

Note 1. Apprentices & probationers shall be treated as temporary employees for the purpose of this rule.

Note 2. A temporary employee who completes one year of continuous service during the middle of a month shall subscribe to the Fund from the subsequent month.

Note 3. Temporary employee (including Apprentices and Probationers) who have been appointed against regular vacancies and are likely to continue for more than a year may subscribe to the General Provident Fund any time before completion of one year's service.

6. **Nomination—**(1) A subscriber shall, at the time of joining the Fund, send to the Account Officer, a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the event of his death, before that amount has become payable or having become payable has not been paid :

Provided that where a subscriber is a minor, he shall be required to make the nomination only his attaining the age of majority :

Provided further that a subscriber who has a family at the time of making the nomination shall make such nomination only in favour of a member or members of his family :

Provided also that the nomination made by the subscriber in respect of any other provident fund to which he was subscribing before joining the Fund shall, if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in the Fund, be deemed to be a nomination duly made under this rule until he makes a nomination in accordance with this rule.

(2) If a subscriber nomination more than one person under sub-rule (1), he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.

(3) Every nomination shall be in the Forms set forth in the First Schedule.

(4)(i) A subscriber may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Account Officer.

(ii) The subscriber shall, along with such notice or separately, send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

(5) A subscriber may provide in a nomination—

(a) in respect of any specified nominee, that in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination:

Provided that such other person or persons, shall if the subscriber has other member of his family be such other member or members.

(b) where the subscriber confers such a right on more than one person under the clause (a) he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of sub-rule (5), the subscriber shall send to the Accounts Officer a notice in writing canceling the nomination together with a fresh nomination made in accordance with the provision of this rule.

(7) Every nomination made, and every notice of the cancellation given by the subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Accounts Officer.

Note : In this rule, unless the context otherwise requires "perso" or "persons" shall include a company or association or body of individuals, whether incorporated or not and shall also include a Fund such the Prime Minister's National Relief Fund or any Chariatable or other Trust or Fund, to which nomination may be made through the Secretary or other executive of the said funds or Trust authorized to receive payments".

7. **Subscriber's Account.**—An account shall be opened in the name of each subscriber in which following shown—

(i) his subscriptions;

(ii) interest, as provided by Rule 12, on subscriptions;

(iii) advances and withdrawals from the Fund,

8. **Conditions of subscriptions.**—(1) A subscriber shall subscribe monthly to the fund except during the period when he is under suspension :

Provided that a subscriber may, at his option, not subscribe during leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half-pay or half-average pay :

Provided further that a subscriber on reinstatement after a period passed under suspension shall be allowed the option of paying in one lump sum, or in installments, any sum not exceeding the maximum amount of arrears subscriptions payable for that period.

Note : 1—The holder of a seasonal post in an establishment need not subscribe to the Fund, during the period of his unemployment.

Note : 2—A subscriber need not subscribe during a period treated as dies non.

(2) The subscriber shall intimate his election not to subscribe during the leave referred to in the first proviso to sub-rule (1) in the following manner :—

- (a) if he is an officer who draws his own bills, by making no deduction on account of subscription in his first pay bill drawn after proceeding on leave;
- (b) if he is not an officer who draws his own pay bills, by written communication to the Head of his Office before he proceeds on leave.

(3) Failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe.

(4) The option of a subscriber intimated under this rule shall be final.

(5) A subscriber who has under rule 19 withdrawn the amount standing to his credit in the Fund shall not subscribe to the Fund after such withdrawal unless he returns to duty.

9. Rates of subscription.—(1) The amount of subscription shall be fixed by the subscriber himself, subject to the following conditions, namely :—

- (a) it shall be expressed in whole rupees;
- (b) it may be any sum, so expressed not less than 6 per cent of his emoluments and not more than his total emoluments:

Provided that in the case of a subscriber who has previously been subscribing to the Board's Contributory Provident Fund at the higher rate of $8\frac{1}{3}$ per cent, it may by any sum, so expressed, not less than $8\frac{1}{3}$ per cent, of his emoluments and not more than his total emoluments;

- (c) when an employee elects to subscribe at the minimum rate of 6 per cent or $8\frac{1}{3}$ per cent as the case may be, the fraction of a rupee will be rounded to the nearest whole rupee, 50 paise counting as the next higher rupee.

(2) For the purpose of sub-rule (1) the emoluments of a subscriber shall be—

- (a) in the case of a subscriber who was in Board's service on the 31st March, of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on that date :

Provided that —

- (i) if the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty;
- (ii) if the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on leave on the said date and continues to be on

leave and has elected to subscribe during such leave, his emoluments shall be the emoluments to which he would have been entitled had he been on duty in India;

(b) in the case of a subscriber who was not in Board's service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on the day he joins the Fund.

(3) The subscriber shall intimate the fixation of the amount of his monthly subscription in each year in the following manner :—

- (a) if he was on duty on the 31st March of the preceding year, by the deduction which he makes in this behalf from his pay bill for that month;
- (b) if he was on leave on the 31st March of the preceding year, and elected not to subscribe during such leave, or was under suspension on that date, by the deduction which he makes in this behalf from his first pay bill after his return to duty;
- (c) if he has entered Board's service for the first time during the year, by the deduction which he makes in this behalf from his pay bill for the month during which he joins the Fund;
- (d) if he was on leave on the 31st March of the preceding year, and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, by the deduction which he causes to be made in this behalf from his salary bill for that month;
- (e) if he was on foreign Service on the 31st March of the preceding year, by the amount credited by him into the Board on account of subscription for the month of April in the current year.

(4) The amount of subscription so fixed may be—

- (a) reduced once at any time during the course of the year;
- (b) enhanced twice during the course of the year; or
- (c) reduced and enhanced as aforesaid :

Provided that when the amount of subscription is so reduced, it shall not be less than the minimum prescribed in sub-rule (1) :

Provided further, that if a subscriber is on leave without pay or leave on half-pay or half average pay for a part of a calendar month and he has elected not to subscribe during such leave, the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty including leave, if any, other than those referred to above.

10. Transfer to foreign service or deputation out of India.—When a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputation out of India, he shall remain subject to the rules of the Fund in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation.

11. Realization of Subscriptions.—(1) The Board shall have power to deduct from the emoluments of any subscriber, the subscription due from him and interest on the advance, if any, made to him from the Fund.

- (2) When emoluments are drawn from any other source the subscriber shall forward his dues monthly to the Accounts Officer :

Provided that in the case of a subscriber on deputation to a body corporate, owned or controlled by the Central Government or the State Government; as the case may be, the subscription shall be recovered and forwarded to the Accounts Officer by such body.

- (3) if a subscriber fails to subscribe with effect from the date on which he is required to join the Fund or is in default in any month or months during the course of a year otherwise than as provided in rule 8, the total amount due to the Fund on Accounts of arrears of subscription shall, with interest thereon at the rate provided in rule 12, forthwith be paid by the subscriber to the fund or in default be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber by instalments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-rule (2) of 13 :

Provided that subscribers whose deposits in the Fund carry no interest shall not be required to pay any interest.

12. Interest.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (5), Board shall pay to the credit of the account of a subscriber interest at such rate as may be determined for each year according to the method of calculation prescribed from time to time by the Central Government :

Provided that a if the rate of interest determined for a year is less than 4 per cent, all subscribers to the Fund in the year preceding that for which the rate has for the first time been fixed at less than 4 per cent, shall be allowed interest at 4 per cent :

Provided further that a subscriber who was previously subscribing to any other provident fund of the Central Government and whose subscription, together with interest thereon, have been transferred to his credit in his Fund under Rule 22, shall also be allowed interest at 4 per cent, if he had been receiving that rate of interest under the rules of such other Fund under a provision similar to that of the first proviso to this rule.

(2) Interest shall be credited with effect from last day in each year in the following manner :—

- (i) on the amount to the credit of a subscriber on the last day of the preceding year, less any sums withdrawn during the current year interest for twelve months;
- (ii) on sums withdrawn during the current year interest from the beginning of the current year upto the last day of the month proceeding the month of withdrawal;
- (iii) on all the sums credited to the subscriber's account after the last day of the preceding year interest from the date of deposit upto the end of the current year;
- (iv) the total amount of interest shall be rounded to the nearest whole rupee, (fifty paise counting as the next higher rupee) :

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under this rule in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, upto the date on which the amount standing to the credit of the subscriber became payable.

- (3) In this rule, the date of deposit shall in the case of recovery from emoluments be deemed to be the first day of the month in which it is recovered, and in the case of an amount forwarded by the subscriber, shall be deemed to be the first day of the month of receipt, if it is received by the Accounts Officer before the fifth day of that month, but if it is received on or after the fifth day of that month, the first day of the next succeeding month :

Provided that where there has been a delay in the drawal of pay or leave salary and allowances of a subscriber and consequently the recovery of his subscription towards the Fund, the interest on such subscriptions shall be payable from the month in which the pay or leave salary of the subscriber was due under the rules, irrespective of the month in which it was actually drawn :

Provided further that in the case of an amount forwarded in accordance with the proviso to sub-rule (2) of rule 11, the date of deposit shall be deemed to be the first day of the month if it is received by the Accounts Officer before the fifteenth day of that month :

Provided also that where the emoluments for a month are drawn and disbursed on the last working day of the same month the date of deposit shall, in the case of recovery of his subscription, be deemed to be the first day of the succeeding month.

- (4) In addition to any amount to be paid under rules 18, 19 or 20 interest thereon up to the end of the

month preceding that in which the payment is made, or upto the end of the sixth month after the month in which such amount became payable whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid :

Provided that where the Accounts Officer has intimated to that person (or is agent) a date on which he is prepared to make payment in cash, or has posted a cheque in payment to that person, interest shall be payable only upto the end of the month preceding the date so intimated, or the date of posting the cheque, as the case may be :

Provided further that where a subscriber on deputation to a body corporate, owned or controlled by the Central Government or the State Government or an autonomous organization registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) is subsequently absorbed in such body corporate or organization with effect from a retrospective date, for the purpose of calculating the interest due on the Fund accumulations of the subscriber, the date of issue of the orders regarding absorption shall be deemed to be the date on which the amount to the credit of the subscriber became payable subject, however, to the condition that the amount recovered as subscription during the period commencing from the date of absorption and ending with the date of issue of orders of absorption shall be deemed to be subscription to the Fund only for the purpose of awarding interest under this sub-rule.

NOTE : Payment of interest on the Fund balance beyond a period of 6 months, may be authorized by the Chairman or any officer authorized by the Chairman, after he has personally satisfied himself that the delay in payment was occasioned by circumstances beyond the control of the subscriber or the person to whom such payment was to be made, and in every such case the administrative delay involved in the matter shall be fully investigated and action, if any required, be taken.

(5) Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he informs the Accounts Officer that he does not wish to receive it; but if he subsequently asks for interest, it shall be credited with effect from the first day of the year in which he asks for it.

(6) The interest on amounts which under sub-rule (3) of Rule 11, Rules 18 or 19 are replaced to the credit of the subscriber in the Fund, shall be calculated at such rates as may be successively prescribed under sub-rule (1) of this rule and so far as may be in the manner described in this rule.

(7) In case a subscriber is found to have drawn from the Fund an amount in excess of the amount standing to his credit on the date of the drawal, the over drawn amount, irrespective of whether the overdrawal occurred in the course of an advance or a withdrawal or the final payment from the fund, shall be repaid by him with interest thereon in one

lump sum or in default, be ordered to be recovered by, deduction in one lump sum from the emoluments of the subscriber.

(8) If the total amount to be recovered is more than half of the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount together with interest, is recovered.

(9) For sub-rule (7), the rate of interest to be charged on overdrawn amount would be two and half per cent over and above the normal rate on Provident Fund balance under sub-rule (1); and the interest realised on the overdrawn amount shall be credited to Board's account under a distinct sub-head "Interest on overdrawals from Provident Fund".

13. Advances from the Fund :—(1) The Chairman or any other Officer of the Board authorised by the Chairman may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding in amount three month's pay or half of amount standing to his credit in the Fund whichever is less, for one or more of the following purposes :—

- (a) to pay expenses in connection with the illness, confinement or a disability, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;
- (b) to meet cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him in the following cases namely:—
 - (i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and
 - (ii) for any medical, engineering other technical or specialised course in India beyond the High School stage:

provided that the course of study is for not less than three years;

- (c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;
- (d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Board's source;
- (e) to meet the cost of the subscriber's defence where he engages a legal practitioner to defend

himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part;

- (f) to purchase consumer durables such as Television, Video Cassette Recorder, Video Cassette player, washing machines, Cooking range, geysers and computers.

(2) The Chairman may in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in sub-rule (1).

(3) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in sub-rule (1) or until repayment of the last installment of any previous advance.

(4) When an advance is sanctioned under sub-rule (2) before repayment of last installment of any previous advance is completed the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the installments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

(5) After sanctioning the advance, the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in case where the application for final payment had been forwarded to the Accounts Officer under clause (i) of sub-rule (3) of Rule 21.

NOTE : 1— For the purpose of this rule, pay includes dearness pay where admissible.

NOTE : 2— The Officers to be authorised to sanction advances under this rule are specified in Schedule II.

NOTE : 3— A subscriber shall be permitted to take an advance once in every six months under clause (b) of sub-rule (1).

14. Recovery of advances— (1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly installments as the sanctioning authority may direct; but such number shall not be less than twelve unless the subscriber so elects and more than twenty-four.

(2) In special cases where the amount of advance exceeds three month's pay of the subscriber under sub-rule (3) of Rule 13, the sanctioning authority may fix such number of installments to be more than twenty-four but in no case more than thirty-six.

(3) A subscriber may, at his option, repay more than one installment in a month; and each installment shall be a number of whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced, if necessary, to admit of the fixation of such installments.

(4) Recovery shall be made in the manner prescribed in Rule 11 for the realisation of subscription, and shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn.

(5) Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent while he is in receipt of subsistence grant or is on leave for ten days or more in a calendar month which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay, as the case may be.

(6) The recovery may be postponed, on the subscriber's written request, by the sanctioning authority during recovery of an advance of pay granted to the subscriber.

(7) If more than one advance has been made to a subscriber, each advance shall be treated separately for the purpose of recovery.

(8) Recoveries made under this rule shall be credited as they are made to the subscriber's account in the fund.

(9) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed, the whole or balance of the amount withdrawn shall forthwith be repaid by the subscriber to the fund, or in default, be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in a lump sum or in monthly installments not exceeding twelve as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which, special reasons are required under sub-rule (3) of Rule 13;

Provided that before such advance is disallowed, the subscriber shall be given an opportunity to explain to the sanctioning authority in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced and an explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days; it shall be referred to the Chairman for decision; and if no explanation within the said period is submitted by him, the repayment of the advance shall be enforced in the manner prescribed in this sub-rule.

15. Wrongful use of Advance— (1) Notwithstanding anything contained in these rules, if the sanctioning authority has reason to doubt that money drawn as an advance from the Fund under Rule 13 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, he shall communicate to the subscriber the reason for his doubt and require him to explain in writing within fifteen days of the receipt of such communication, whether the advance has been utilized for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money.

1179 9/7/2005-8

- (2) If the sanctioning authority is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of fifteen days, it shall direct the subscriber to repay the amount in question to the fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in one sum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave.
- (3) If the total amount to be repaid were more than half the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly installments of moieties of his emoluments till the entire amount is repaid by him.

NOTE: The term "emoluments" in the rule does not include subsistence grant.

- 16 Withdrawals from the fund :- (1) Subject to the conditions specified therein, withdrawals may be sanctioned by the Chairman or sanctioning authority, at any time.—

- (A) After the completion of fifteen years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely:—

- (a) meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely:—

- (i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and
- (ii) for any medical engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage;

- (b) meeting the expenditure in connection with the betrothal or marriage of the subscriber or his son or his daughters, and any other female relation actually dependent on him;

- (c) meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, travelling expenses, of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

- (d) meeting the cost of consumer durable such as Television, Video Cassette Recorder, Video Cassette player, washing machines, cooking range, geysers and computers;

- (B) During the service of a subscriber from the amount standing to his credit the Fund for one or more of the following purposes, namely:—

- (a) building or acquiring a suitable house or ready built flat for his residence including the cost of the site or any payment towards allotment of a plot or flat by an Authority, State Housing Board or a House Building Society;

- (b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence;

- (c) purchasing a house-site building a house thereon for his residence or repaying outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose;

- (d) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber;

- (e) renovating, additions or alterations or upkeep of the ancestral house or a house built with the assistance or loan from Board;

- (f) constructing a house on a site purchased under Clause (c);

- (C) Within twelve months before the date of subscriber's retirement on superannuation from the amount standing to the credit in the fund, without linking to any purpose;

- (D) Once during the course of a financial year, an amount equivalent to one year's subscription paid for by the subscriber towards the Group Insurance Scheme for the Central Government employees on self-financing and contributory basis.

NOTE 1- (a) a subscriber who has availed himself of an advance under the Scheme of the Ministry of Urban Development for the grant of advance for house-building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other Board source, shall be eligible for the grant of final withdrawal under sub-clauses (a), (c) (d) and (f) of Clause (B) for the purposes specified therein and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid Scheme subject to the limit specified in the proviso to the sub-rule (1) of Rule 17;

(b) if a subscriber has an ancestral house, or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Government, he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under sub clauses (a), (c) and (f) of Clause (B) for purchase of a house-site or for construction of another house or for acquiring a ready-built flat at the place of his duty.

NOTE : 2- Withdrawal under sub-clauses (a), (d), (e) or (f) of Clause (B) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

NOTE : 3 The amount of withdrawal sanctioned under sub-clause (b) of Clause (B) shall not exceed $\frac{3}{4}$ of the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clause (a), reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is $\frac{3}{4}$ of the balance as on date plus amount of previous withdrawal (s) for the house in question minus the amount of the previous withdrawal(s).

NOTE:4- Withdrawal under sub clause (a) or (d) of Clause (B) shall also be allowed where the house-site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

NOTE:5- (a) only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this rule; but marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat covered by a fresh plan duly approved by the local Municipal Body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose ;

(b) Withdrawal for meeting the cost of education of a child may be allowed on annual basis till the concerned child continues to pursue the technical or professional course ;

(c) Second or subsequent withdrawal under sub Clause (a) or (f) of clause (B) for completion of the same house shall be allowed up to the limit laid down under note (3).

NOTE:6- A withdrawal under this rule shall not be sanctioned if an advance under Rule 13 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

(2) Whenever a subscriber is in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit in the General Provident Fund Account with reference to the latest available statement of General Provident Fund Account together with the evidence of subsequent contribution, the competent authority may itself sanction withdrawal within the prescribed limits, as in the case of a refundable advance. In doing so, the competent authority shall take into account any withdrawal or refundable advance already sanctioned by it in favour of the subscriber.

(3) Where the subscriber is not in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit or where there is any doubt about the admissibility of the withdrawal applied for, a reference may be made to the Accounts Officer by the competent authority for ascertaining the amount standing to the credit of the subscriber with a view to enable the competent authority to determine the admissibility of the amount withdrawal.

(4) The sanction for the withdrawal should prominently indicate the General Provident Fund Account Number and the Accounts Officer maintaining the accounts and a copy of the sanction should invariably be endorsed to that Accounts Officer ; and the sanctioning authority shall be responsible to ensure that an acknowledgement is obtained from the Accounts Officer that the sanction for withdrawal has been noted in the ledger account of the subscriber.

(5) In case the Accounts Officer reports that the withdrawal as sanctioned is in excess of the amount to the credit of the subscriber or otherwise inadmissible, the sum withdrawn by the subscriber shall forthwith be repaid in one lump sum by the subscriber to the Fund and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly installments as may be determined by the Chairman.

(6) After sanctioning the withdrawal the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in cases where the application for final payment had been forwarded to the Accounts Officer under Clause (i) of sub-rule (3) of Rule 22.

17. Conditions for withdrawal :-(1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for or more of the purposes specified in Rule 16 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one half of such amount or six months' pay, whichever is less:

Provided that the sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto 3/4 of the balance at his credit in the Fund having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made; (ii) the status of the subscriber; and (iii) the amount to his credit in the Fund in case of withdrawal under Clause (A) and upto 90% of balance at credit in cases of withdrawals under Clause (B) of sub-rule (1) of rule 16:

Provided further that in no case the maximum withdrawal for purposes specified in Clause (B) of sub-rule (1) of Rule 16 shall exceed the maximum limits prescribed from time to time Rules 2 (a) and 3 (b) of the Scheme of the Ministry of Urban Development for the grant of advances for house-building purposes:

Provided also that in the case of a subscriber who has availed himself of an advance under the scheme of the Ministry of Urban Development for the grant of advance for house building purposes, or has been allowed any assistance in this regard from any other government source, the sum withdrawn under this sub-rule with the amount of advance taken under the aforesaid scheme of the assistance taken from any other government source shall not exceed Rs.75000/- (Rupees seventy five thousand) only or five years pay, whichever is less:

Provided also that in the case of a subscriber who has availed himself of an advance under the Scheme of the Ministry of Urban Development for the grant of advances for house-building purposes, or has been allowed any assistance in this regard from any other Board's source, the sum withdrawn under this sub-rule together with the amount of advance taken under the aforesaid Scheme or the assistance taken from any other Board source shall not exceed the maximum limit prescribed from time to time under Rules 2 (a) and 3 (b) of the aforesaid Scheme:

Provided also that the withdrawal admissible under Rule 16 (1) (c) shall not exceed 90% of the amount standing to the credit of the subscriber in the fund.

NOTE:1- A withdrawal to a subscriber under sub-clause (a) of Clause (A) of sub-rule (1) of Rule 16, may be permitted annually so long as the concerned child of the subscriber continues to pursue the course.

NOTE:2- In cases where a subscriber has to pay in installments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed through any Development Authority or a State Housing Board or a House Building Co-operative Society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment in any installment and every such payment shall be treated as a payment for separate purposes of sub-rule (1) of Rule 17.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under rule 16 shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilized for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn, or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lump-sum together with interest thereon at the rate determined under Rule 12 by the subscriber to the fund; and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump-sum or in such number of monthly installments, as may be determined by the Chairman:

Provided that, before repayment of a withdrawal is enforced under this sub-rule, the subscriber shall be given an opportunity to explain in writing within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced, and if the sanctioning authority is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall enforce the repayment in the manner specified in this sub-rule.

(3) (a) A subscriber who has been permitted under sub clause (a), sub-clause (b) or sub-clause (c) of (B) of sub-rule (1) of Rule 16 to withdraw money from the amount standing to his credit in the Fund, shall not part with the possession of the House built or acquired or house site purchased with money so withdrawn, whether by way of sale, mortgage (other than mortgage to the Board), gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the Chairman:

Provided that, such permission shall not be necessary for—

(i) the house or house site being leased for any term not exceeding 3 years; or

(ii) its being mortgaged in favour of a Housing Board, Nationalized Banks, the Life Insurance Corporation owned or controlled by the Central Government which advances, loans for the construction of a new house or for making additions or alteration to an existing house;

(b) the subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December of every year as to whether the house or the house site, as the case may be, continues to be in his possession or has been mortgaged, otherwise transferred or let out as aforesaid and shall if so required, produce before the sanctioning authority on or before the date specified by that authority in that behalf, the original sale, mortgage or lease deed and also the documents on which his title to the property is based:

(c) if, at any time, before his retirement, the subscriber parts with the possession of the house or house site without obtaining the previous permission of the chairman, he shall forthwith repay the sum so withdrawn by him in a lump sum to the Fund, and in default of such repayment, the sanctioning authority, after giving the subscriber a reasonable opportunity of making a representation in the matter, cause the said sum to be recovered from the emoluments of the subscriber either in

a lump sum or in such number of monthly installments, as may be determined by it.

NOTE: A subscriber who has taken loan from Board and in lieu thereof mortgaged the house or house site the Board shall be required to furnish the declaration to the following effect, namely:—

“I do hereby certified that the house or house site for the construction of which or for the acquisition of which I have taken a final withdrawal from the Provident Fund continues to be in my possession but stands mortgaged to Board”.

18. Conversion of an Advance into Withdrawal. - A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under Rule 13 for any of the purposes specified in sub-rule (1) of Rule 16 may convert, at his discretion by written request addressed to the Accounts Officer through the sanctioning authority, the balance outstanding against it into a final withdrawal on his satisfying the condition laid down in Rules 16 and 17.

NOTE: 1—The Head of Office may be asked by the Accounts Officer to stop recoveries from the pay bills when the application for such conversion is forwarded to the Accounts Officer by that authority.

NOTE: 2—For the purpose of sub-rule (1) of Rule 17, the amount of subscription with interest thereon standing to the credit of the subscriber in the account at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance; and each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion.

19. Final withdrawal of accumulations in the fund:— When a subscriber quits the service, the amount standing to his credit in the Fund shall become payable to him:

Provided that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated in the service shall, if required to do so by the Board, repay any amount paid to him from the Fund in pursuance of this rule, with interest thereon at the rate provided in rule 12 in the manner provided in the proviso to rule 19; and the amount so repaid shall be credited to his account in the Fund.

Explanation-I.— A subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently reemployed, with or without a break in service, shall not be deemed to quit the service, when he is transferred without any break in service to a new post under a State Government or in another department of the Central Government (in which he is governed by another set of Provident Fund Rule) and without retaining any connections with his former post. In such case, his subscriptions together with interest thereon shall be transferred—

(a) To his account in the other Fund in accordance with the rules of the Fund, if the new post is in another department of the Central Government; or

(b) To a new account under the State Government concerned if the new post is under a State Government and the state Government consents, by general or special order, to such transfer of his subscription and interest.

NOTE :—Transfers shall include cases of resignation from service in order to take up appointment in another Department of the Central Government or under the State Government without any break and with proper permission of the Chairman.

Provided that in cases where there has been a break in service it shall be limited to the joining time allowed on transfer to a different station.

Explanation-II.—When a subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed, is transferred, without any break, to the service under a body corporate owned or controlled by the Central Government or the State Government or an autonomous organization, registered under the Societies Registration Act, 1860, the amount of subscriptions together with interest thereon, shall not be paid to him but shall be transferred with the consent of the body, to his new Provident Fund account under that body.

NOTE :—Transfers shall include cases of resignation from service in order to take up appointment under a body corporate owned or controlled by the Central Government or the State Government or an autonomous organization, registered under the Societies Registration Act, 1860, without any break and with proper permission of the Board.

Provided that the time taken to join the new post shall not be treated as a break in service if it does not exceed the joining time admissible to a Board employee on transfer from one post to another.

Provided further that the amount of subscription together with interest thereon, of a subscriber opting for service under Public Enterprise may.—

(i) if he so desires, be transferred to his new Provident Fund Account under the Enterprise if the concerned Enterprise also agrees to such a transfer;

(ii) if the subscriber does not desire the transfer or the concerned Enterprise does not operate a Provident Fund, the amount aforesaid shall be refunded to the subscriber.

20. Retirement of Subscriber :—When a Subscriber—

(a) has proceeded on leave preparatory to retirement, or

(b) while on leave, has been permitted to retire or been declared by a competent medical authority to be unfit for further service.

The amount standing to his credit in the Fund shall, upon application made by him in that behalf to the Accounts Officer, become payable to the subscriber:

Provided that the subscriber, if he returns to duty, shall, if required to do so by the Board, repay to the Fund for credit to his account, the whole or part of any amount paid to him from the fund in pursuance of this rule with interest thereon at the rate provided in rule 12 in cash or securities or partly in cash or partly in securities, by instalments or otherwise, by recovery from his employments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which, special reasons are required under sub-rule (2) of rule 13.

21. Procedure on the death of a subscriber.—On the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable, before payment has been made :

(1) When the subscriber leaves a family—

(a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of rule 6 or of the corresponding rule heretofore in force in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination ;

(b) if no such nomination in favour of a member or members of the family of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares:

Provided that no share shall be payable to—

- (i) sons who have attained majority;
- (ii) sons of a deceased son who have attained majority;
- (iii) married daughters whose husbands are alive;
- (iv) married daughters of a deceased son whose husbands are alive;

if there is any member of the family other than those specified in clauses (i), (ii), (iii) & (iv) :

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) of the first proviso;

(2) When the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of rule 6 or of the corresponding rule heretofore in force in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

22. Manner of payment of amount in the Fund.—(1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the fund becomes payable, it shall be the duty of the Accounts Officer to make payment on receipt of a written application in this behalf as provided in sub-rule (3).

(2) If the person to whom, under these rules, any amount or policy, is to be paid, assigned or reassigned or delivered, is a lunatic for whose estate a Manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912, the payment or reassignment or delivery shall be made to such Manager and not to the lunatic :

Provided that where no Manager has been appointed and the person to whom the sum is payable is certified by a Magistrate to be a lunatic, the payment shall under the orders of the Collector be made in terms of sub-section (1) of Section 95 of the Indian Lunacy Act, 1912, to the person having charge of such lunatic and the Accounts Officer shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the lunatic and the surplus, if any, or such part thereof, as he thinks fit, shall be paid for the maintenance of such members of the lunatic's family as are dependent on him for maintenance.

(3) Payments of the amount withdrawn shall be made in India only; and the persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive payments in India.

(4) The following procedure shall be adopted for claiming payment by a subscriber, namely :—

- (i) the Head of Office/Department shall forward the details of the subscriber retiring or quitting service to the Accounts Officer indicating the recoveries effected against the advances which are still current and the number of instalments yet to be recovered and also indicate the withdrawals, if any, taken by the subscriber after the period covered by the last statement of the subscriber's account sent by the Accounts Officer;
- (ii) the Accounts Officer shall, after verification with the ledger account, issue an authority for the amount payable to the subscriber at least a month before the date of superannuation but payable on the date of superannuation;
- (iii) the authority mentioned in Clause (ii) will constitute the first instalment of payment and a second authority for payment will be issued as soon as possible after superannuation which will relate to the contribution made by the subscriber subsequent to the amount mentioned in the details forwarded by the Head of Office/Department under Clause (ii) plus the refund of instalments against advance which were current at the time of the submission of details by the Head of Office.
- (iv) after forwarding the details referred to in Clause (ii) for final payment to the Accounts Officer, advance/withdrawal may be sanctioned but the amount of advance/withdrawal shall be drawn on an authorization from the Accounts Officer concerned who shall arrange this as soon as the formal sanction of sanctioning authority is received by him.

NOTE : When the amount standing to the credit of a subscriber has become payable under rules 18, 19 or 20 the Accounts Officer shall authorize prompt payment of the amount in the manner indicated in sub-rule (3).

23. Procedure on transfer to Board's service of a person from the service under a body corporate owned or

controlled by Government.—If a Board employee admitted to the benefit of the Fund was previously a subscriber to any Provident Fund of a body corporate owned or controlled by the Central Government or a State Government, or an organization registered under the Societies Registration Act, 1860, the amount of subscriptions, together with interest thereon, standing to his credit in such other fund on the date of transfer shall be transferred to his credit in the Fund :

Provided that where a subscriber was subscribing to a non-Contributory Provident Fund of a State Government, the consent of that Government shall be obtained.

24. Relaxation of the provisions of the rule in individual cases.—When the Board is satisfied that the operation of any of these rules causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber, Board may, notwithstanding anything contained in these rules deal with the case of such subscriber in such manner as may appear to them to be just and equitable.

25. Annual Statement of account to be supplied to subscriber.—(1) As soon as possible after the 31st March of each year, the Accounts Officer shall send to each subscriber a statement of his account in the Fund showing the opening balance as on the 1st April of the year, the total amount credited or debited during the year, the total amount of interest credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date and shall attach to the statement of accounts an enquiry whether the subscriber—

- (a) desires to make any alteration in any nomination made under Rule 6;
- (b) has acquired a family in cases where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under the proviso to sub-rule (1) of Rule 6.

(2) Subscribers should satisfy themselves as to the correctness of the annual statement and errors should be brought to the notice of the Accounts Officer within three months from the date of the receipt of the statement.

(3) The Accounts Officer shall, if required by a subscriber once, but not more than once, in a year inform the subscriber of the total amount standing to his credit in the Fund at the end of the last month for which his account has been written up.

26. Number of account to be quoted at the time of the payment of subscription.—When paying a subscription in India, either by deduction from emoluments or in cash, a subscriber shall quote the number of his account in the Fund, communicated to him by the Accounts Officer; and any change in the number shall similarly be communicated to the subscriber by the Accounts Officer.

27. Maintenance of accounts.—(1) All sums paid into and from the Fund under these rules shall be accounted for in the books of the Board in an account named "The Coffee Board General Provident Fund Account".

(2) Such accounts shall be examined and audited annually by the auditors appointed under Section 45(3) of the Coffee Act.

(3) The custody and disbursal of the Fund shall be regulated by Rule 35 of the Coffee Rules, 1955, exactly in the same manner as the Funds of the Board.

(4) All expenses of the Fund shall be met from the income of the Fund, as far as possible :

Provided that the deficit shall be met from the General Fund, if the income is not sufficient to meet all expenses.

28. Winding up of the fund.— (1) The Fund shall be wound up

- (a) if the Board is to be dissolved by Notification under Section 10 of the Act; or
- (b) by resolution of the Board approved by the Central Government.

(2) On the winding up of the Fund, the assets shall be realised and distributed amongst subscribers in accordance with their accounts :

29. Repeal and saving.— (1) The Coffee Board General Provident Fund Rules, 1965 is hereby repealed :

Provided that such repeal shall not affect —

- (a) the previous operation of the said Rules or anything duly done or suffered therein; or
- (b) any right obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Rules; or
- (c) any recovery in respect of any wrongful use of advance.

29. Interpretation.— If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government for its decision.

[No. 9/3/99—Plant (B)]

A. SENGUPTA, Addl. Secy.

COFFEE BOARD GENERAL PROVIDENT FUND RULES, 2004

First Schedule

(see sub-rule 3 of rule 6)

Subscriber's Name Shri/Smt.

Depositor Account No.

Nomination Register Folio No.

SUBSCRIBER'S NOMINATION

I. When the subscriber has a family and wishes to nominate one member thereof.

I hereby nominate the person mentioned below who is a member of my family as defined in rule 2 of the Coffee Board General Provident Fund Rules, 2004 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid :—

1. Name and address of the nominee in the event of subscriber's death
2. Relationship with subscriber
3. Age
4. Name, address and relationship of person, or persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass, in the event of his predeceasing the subscriber.

Dated this day of 20

at

Signature of subscriber

Designation

Address

Signature of two witnesses with addresses :

(1)

(2)

N.B. :— The Subscriber should draw lines across the blank space below his last entry to prevent insertion of any names after he has signed.

Col. No. 4 should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber in the Fund at any time.

Subscriber's Name Shri/Smt.

Depositor Account No.

Nomination Register Folio No.

SUBSCRIBER'S NOMINATION

II. When the subscriber has a family and wishes to nominate more than one member thereof.

I hereby nominate the persons mentioned below who are the members of my family as defined in rule 2 of the Coffee Board General Provident Fund Rules 2004 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown below against their names :—

1. Name and address of the nominees in the event of the subscriber's death
2. Relationship with subscriber
3. Age
4. Amount of share of accumulations to be paid to each
5. Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid.
6. Name, address and relationship of the person, or persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber.

Dated this day of 20

at

Signature of subscriber

Designation

Address

Signature of two witnesses with addresses :

(1)

(2)

N. B. :—The Subscriber should draw lines across the blank space below his last entry to prevent insertion of any names after he has signed.

Col. No. 4 should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber in the Fund at any time.

Subscriber's Name Shri/Smt.

Depositor Account No.

Nomination Register Folio No.

SUBSCRIBER'S NOMINATION

III. When the subscriber has no family and wishes to nominate one person.

I, having no family as defined in rule 2 of the Coffee Board General Provident Fund Rules 2004, hereby nominate the person mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid.

1. Name and address of the nominee
2. Relationship with subscriber
3. Age
4. Contingencies (**) on the happening of which the nomination shall become invalid.
5. Name, address and relationship of the person, or persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber.

Dated this day of 20

at

Signature of subscriber

Designation

Address

Signature of two witnesses with addresses :

(1)

(2)

Note :— Where a subscriber who has no family makes a nomination, he will specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.

N.B. :— The Subscriber should draw lines across the blank space below his last entry to prevent insertion of any names after he has signed.

Col. No. 4 should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber in the Fund at any time.

Subscriber's Name Shri/Smt. Depositor Account No.
Nomination Register Folio No.

SUBSCRIBER'S NOMINATION

IV. When the subscriber has no family and wishes to nominate more than one person.

I, having no family as defined in rule 2 of the Coffee Board General Provident Fund Rules 2004, hereby nominate the person mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown below against their names :—

1. Name and address of the nominee in the event of subscriber's death
2. Relationship with subscriber
3. Age
4. *Amount of share of accumulations to be paid to each
5. **Contingencies (**) on the happening of which the nomination shall become invalid.
6. Name, address and relationship of the person, or persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber.

Dated this day of 20

at

Signature of subscriber

Designation

Address

Signature of two witnesses with addresses :

(1)

(2)

N.B. :— The Subscriber should draw lines across the blank space below his last entry to prevent insertion of any names after he has signed.

Col. No. 4 should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber in the Fund at any time.

Where a subscriber who has no family makes a nomination, he shall specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.

COFFEE BOARD GENERAL PROVIDENT FUND RULES, 2004

Second Schedule

(See Note 2 of rule 13)

AUTHORITIES COMPETENT TO GRANT TEMPORARY ADVANCES

In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 13 of the Coffee Board General Provident Fund Rules, 2004, the Chairman hereby delegates his powers to grant advances to Class III and Class IV staff under their control for which special reasons are not required under sub-rule (2) to the following Officers—

1. Secretary
2. Director of Finance
3. Director of Promotion
4. Director of Research
5. Accounts Officer

6. All Class II Officers empowered to sanction advance of T. A. to their staff on transfer.

All advances to Class II Officers and advances for special reasons under sub-rule (2) of rule 13 will be sanctioned by the *Chairman* only.

CHAIRMAN

1179 57/2005-10

शहरी विकास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 133.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपदा निदेशालय, समूह-घ (मुख्यालय) (भर्ती) (संशोधित) नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (अ) इन नियमों का नाम संपदा निदेशालय, समूह-घ (मुख्यालय) (भर्ती) (संशोधित) नियम, 2005 है।

(ब) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संपदा निदेशालय समूह-घ (मुख्यालय) भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

स्तंभ 5—वरिष्ठता आधारित चयन या योग्यता आधारित चयन पद के स्थान पर चयन।

[मिसिल सं. ए-12018/1/2000-प्रशा. ख]

एन.एन. माथुर, अपर संपदा निदेशक (स्थापना)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Directorate of Estates)

New Delhi, the 13th April, 2005

G.S.R. 133.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Estates (Class-IV) (Headquarters) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2001.

1. (a) These rules may be called the Directorate of Estates, (Class-IV) (Headquarters) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2005.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Estates, (Class-IV) (Headquarters), Recruitment Rules, 2001, following entry shall be substituted :—

Column 5—‘Selection’ instead of ‘Selection-cum-seniority or Selection by merit’.

[F. No. A-12018/1/2000-Adm. B]

N.N. MATHUR, Addl. Director of Estates (Estt.)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 134.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपदा निदेशालय, किराया संग्रहाक (भर्ती) (संशोधित) नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (अ) इन नियमों का नाम संपदा निदेशालय, किराया संग्रहाक (भर्ती) (संशोधित) नियम, 2005 है।

(ब) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संपदा निदेशालय किराया संग्रहाक भर्ती नियम, 2001, की अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

स्तंभ 4—वरिष्ठता आधारित चयन या योग्यता आधारित चयन पद के स्थान पर चयन।

[मिसिल सं. ए-12018/1/2000-प्रशा. ख]

एन.एन. माथुर, अपर संपदा निदेशक (स्थापना)

New Delhi, the 13th April, 2005

G.S.R. 134.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Estates, Rent Collector (Recruitment) (Amendment) Rules, 2001.

1. (a) These rules may be called the Directorate of Estates, Rent Collector (Recruitment) (Amendment) Rules, 2005.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Estates, Rent Collector, Recruitment Rules, 2001, following entry shall be substituted :—

Column 4—‘Selection’ instead of ‘Selection-cum-seniority or Selection by merit’.

[F. No. A-12018/1/2000-Adm. B]

N.N. MATHUR, Addl. Director of Estates (Estt.)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 135.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपदा निदेशालय, डिस्पैच राईडर (भर्ती) (संशोधित) नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (अ) इन नियमों का नाम संपदा निदेशालय, डिस्पैच राईडर (भर्ती) (संशोधित) नियम, 2005 है।

(ब) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संपदा निदेशालय डिस्पैच राईडर भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

स्तंभ 5—वरिष्ठता आधारित चयन या योग्यता आधारित चयन पद के स्थान पर चयन।

[मिसिल सं. ए-12018/1/2000-प्रशा. ख]

एन.एन. माथुर, अपर संपदा निदेशक (स्थापना)

New Delhi, the 13th April, 2005

G.S.R. 135.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Estates, Dispatch Rider (Recruitment) (Amendment) Rules, 2001.

1. (a) These rules may be called the Directorate of Estates, Dispatch Rider (Recruitment) (Amendment) Rules, 2005.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Estates, Dispatch Rider Recruitment Rules, 2001, following entry shall be substituted :—

Column 5—‘Selection’ instead of ‘Selection-cum-seniority or Selection by merit’.

[F. No. A-12018/1/2000-Adm. B]

N.N. MATHUR, Addl. Director of Estates (Estt.)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 136.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपदा निदेशालय, स्टाफ कार ड्राइवर (भर्ती)(संशोधित) नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (अ) इन नियमों का नाम संपदा निदेशालय, स्टाफ कार ड्राइवर (भर्ती)(संशोधित) नियम, 2005 है।

(ब) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संपदा निदेशालय स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियम 2001 की अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

स्तंभ 5—वरिष्ठता आधारित चयन या योग्यता आधारित चयन पद के स्थान पर चयन।

[मिसिल सं. ए-12018/1/2000-प्रशा. ख]

एन.एन. माथुर, अपर संपदा निदेशक (स्थापना)

New Delhi, the 13th April, 2005

G.S.R. 136.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Estates, Staff Car Driver (Recruitment) (Amendment) Rules, 2001.

1. (a) These rules may be called the Directorate of Estates, Staff Car Driver (Recruitment) (Amendment) Rules, 2005.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the schedule to the Directorate of Estates, Staff Car Driver Recruitment Rules, 2001, following entry shall be substituted :—

Column 5—‘Selection’ instead of ‘Selection-cum-seniority or Selection by merit’.

[F. No. A-12018/1/2000-Adm. B]

N.N. MATHUR, Addl. Director of Estates (Estt.)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 137.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपदा निदेशालय, टेली क्लर्क (भर्ती)(संशोधित) नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (अ) इन नियमों का नाम संपदा निदेशालय, टेली क्लर्क (भर्ती)(संशोधित) नियम, 2005 है।

(ब) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संपदा निदेशालय टेली क्लर्क भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

स्तंभ 4—वरिष्ठता आधारित चयन या योग्यता आधारित चयन पद के स्थान पर चयन।

[मिसिल सं. ए-12018/1/2000-प्रशा. ख]

एन.एन. माथुर, अपर संपदा निदेशक (स्थापना)

New Delhi, the 13th April, 2005

G.S.R. 137.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Estates (Tally Clerk) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2001.

1. (a) These rules may be called the Directorate of Estates, (Tally Clerk) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2005.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Estates (Tally Clerk) Recruitment Rules, 2001, following entry shall be substituted :—

Column 4—‘Selection’ instead of ‘Selection-cum-seniority or Selection by merit’.

[F. No. A-12018/1/2000-Adm. B]

N.N. MATHUR, Addl. Director of Estates (Estt.)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 138.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपदा निदेशालय, संपदा सहायक निदेशक (पूछताछ) (भर्ती) (संशोधित) नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (अ) इन नियमों का नाम संपदा निदेशालय, संपदा सहायक निदेशक (पूछताछ) (भर्ती) (संशोधित) नियम, 2005 है।

(ब) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संपदा निदेशालय संपदा सहायक निदेशक (पूछताछ) भर्ती नियम 2001 की अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

स्तंभ 5—वरिष्ठता आधारित चयन या योग्यता आधारित चयन पद के स्थान पर चयन।

[मिसिल सं. ए-12018/1/2000-प्रशा. ख]

एन.एन. माथुर, अपर संपदा निदेशक (स्थापना)

New Delhi, the 13th April, 2005

G.S.R. 138.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Estates, Asstt. Director of Estates (Enquiries) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2001.

1. (a) These rules may be called the Directorate of Estates, Asstt. Director of Estates (Enquiries) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2005.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Directorate of Estates, Asstt. Director of Estates (Enquiries) Recruitment Rules, 2001, following entry shall be substituted :—

Column 5—‘Selection’ instead of ‘Selection-cum-seniority or Selection by merit’.

[F. No. A-12018/1/2000-Adm. B]

N.N. MATHUR, Addl. Director of Estates (Estt.)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 139.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपदा निदेशालय, संपदा उप निदेशक (किराया) (भर्ती) (संशोधित) नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (अ) इन नियमों का नाम संपदा निदेशालय, संपदा उप निदेशक (किराया) (भर्ती) (संशोधित) नियम, 2005 है।

(ब) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संपदा निदेशालय संपदा उपनिदेशक (किराया) भर्ती नियम 2001 की अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

स्तंभ 5—वरिष्ठता आधारित चयन या योग्यता आधारित चयन पद के स्थान पर चयन।

[मिसिल सं. ए-12018/1/2000-प्रशा. ख]

एन.एन. माथुर, अपर संपदा निदेशक (स्थापना)

New Delhi, the 13th April, 2005

G.S.R. 139.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Estates, Dy. Director of Estates (Rents) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2001.

1. (a) These rules may be called the Directorate of Estates, Dy. Director of Estates (Rents) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2005.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Directorate of Estates, Dy. Director of Estates (Rents) Recruitment Rules, 2001, following entry shall be substituted :—

Column 5—‘Selection’ instead of ‘Selection-cum-seniority or Selection by merit’.

[F. No. A-12018/1/2000-Adm. B]

N.N. MATHUR, Addl. Director of Estates (Estt.)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 140.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपदा निदेशालय, संपदा उप निदेशक (भर्ती) (संशोधित) नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (अ) इन नियमों का नाम संपदा निदेशालय, संपदा उप निदेशक (भर्ती) (संशोधित) नियम, 2005 है।

(ब) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संपदा निदेशालय संपदा सहायक निदेशक भर्ती नियम 2001 की अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

स्तंभ 5—वरिष्ठता आधारित चयन या योग्यता आधारित चयन पद के स्थान पर चयन।

[मिसिल सं. ए-12018/1/2000-प्रशा. ख]

एन.एन. माथुर, अपर संपदा निदेशक (स्थापना)

New Delhi, the 13th April, 2005

G.S.R. 140.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Estates, Dy. Director of Estates (Recruitment) (Amendment) Rules, 2001.

1. (a) These rules may be called the Directorate of Estates, Dy. Director of Estates (Recruitment) (Amendment) Rules, 2005.

(b) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Directorate of Estates, Dy. Director of Estates Recruitment Rules, 2001, following entry shall be substituted :—

Column 5—'Selection' instead of 'Selection-cum-seniority or Selection by merit'.

[F. No. A-12018/1/2000-Adm. B]

N.N. MATHUR, Addl. Director of Estates (Estt.)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 141.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपदा निदेशालय, स्वागती (सरकारी होस्टल) (भर्ती) (संशोधित) नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (अ) इन नियमों का नाम संपदा निदेशालय, स्वागती (सरकारी होस्टल) (भर्ती) (संशोधित) नियम, 2005 है।

(ब) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संपदा निदेशालय स्वागती (सरकारी होस्टल) भर्ती नियम 2001 की अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :

स्तंभ 4—वरिष्ठता आधारित चयन या योग्यता आधारित चयन पद के स्थान पर चयन।

[मिसिल सं. ए-12018/1/2000-प्रशा. ख]

एन.एन. माथुर, अपर संपदा निदेशक (स्थापना)

New Delhi, the 13th April, 2005

G.S.R. 141.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Estates, Receptionist (Govt. Hostel) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2001.

1. (a) These rules may be called the Directorate of Estates, Receptionist (Govt. Hostel) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2005.

(b) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Directorate of Estates, Receptionist (Govt. Hostel) Recruitment Rules, 2001, following entry shall be substituted :—

Column 4—'Selection' instead of 'Selection-cum-seniority or Selection by merit'.

[F. No. A-12018/1/2000-Adm. B]

N.N. MATHUR, Addl. Director of Estates (Estt.)

1179 917/2005-11

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 142.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपदा निदेशालय, बेदखली निरीक्षक (भर्ती) (संशोधित) नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (अ) इन नियमों का नाम संपदा निदेशालय, बेदखली निरीक्षक (भर्ती) (संशोधित) नियम, 2005 है।

(ब) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संपदा निदेशालय बेदखली निरीक्षक भर्ती नियम 2001 की अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

स्तंभ 5—वरिष्ठता आधारित चयन या योग्यता आधारित चयन पद के स्थान पर चयन।

[मिसिल सं. ए-12018/1/2000-प्रशा. ख]

एन.एन. माथुर, अपर संपदा निदेशक (स्थापना)

New Delhi, the 13th April, 2005

G.S.R. 142.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Estates, (Eviction Inspector) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2001.

1. (a) These rules may be called the Directorate of Estates, (Eviction Inspector) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2005.

(b) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Directorate of Estates, (Eviction Inspector) Recruitment Rules, 2001, following entry shall be substituted :—

Column 5—'Selection' instead of 'Selection-cum-seniority or Selection by merit'.

[F. No. A-12018/1/2000-Adm. B]

N.N. MATHUR, Addl. Director of Estates (Estt.)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 143.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपदा निदेशालय, मुख्य अधीक्षक एवं अधीक्षक (सरकारी होस्टल) (भर्ती) (संशोधित) नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (अ) इन नियमों का नाम संपदा निदेशालय, मुख्य अधीक्षक एवं अधीक्षक (सरकारी होस्टल) (भर्ती) (संशोधित) नियम, 2005 है।

(ब) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संपदा निदेशालय मुख्य अधिक्षक एवं अधिक्षक (सरकारी होस्टल) भर्ती नियम 2001 की अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

स्तंभ 5-वरिष्ठता आधारित चयन या योग्यता आधारित चयन पद के स्थान पर चयन।

[मिसिल सं. ए-12018/1/2000-प्रशा. ख]

एन.एन. माथुर, अपर संपदा निदेशक (स्थापना)

New Delhi, the 13th April, 2005

G.S.R. 143.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Estates, Chief Superintendent and Superintendent (Govt. Hostel) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2001.

1. (a) These rules may be called the Directorate of Estates, Chief Superintendent and Superintendent (Govt. Hostel) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2005.

(b) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Directorate of Estates, Chief Superintendent and Superintendent (Govt. Hostel) Recruitment Rules, 2001, following entry shall be substituted :—

Column 5—‘Selection’ instead of ‘Selection-cum-seniority or Selection by merit’.

[F. No. A-12018/1/2000-Adm. B]

N.N. MATHUR, Addl. Director of Estates (Estt.)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 144.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपदा निदेशालय, संपर्क अधिकारी (सांसद) (भर्ती)(संशोधित) नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (अ) इन नियमों का नाम संपदा निदेशालय, संपर्क अधिकारी (सांसद) (भर्ती)(संशोधित) नियम, 2005 है।

(ब) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संपदा निदेशालय संपर्क अधिकारी (सांसद) भर्ती नियम 2001 की अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

स्तंभ 5-वरिष्ठता आधारित चयन या योग्यता आधारित चयन पद के स्थान पर चयन।

[मिसिल सं. ए-12018/1/2000-प्रशा. ख]

एन.एन. माथुर, अपर संपदा निदेशक (स्थापना)

New Delhi, the 13th April, 2005

G.S.R. 144.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Estates, Liaison Officer (Parliament) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2001.

1. (a) These rules may be called the Directorate of Estates, Liaison Officer (Parliament) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2005.

(b) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Directorate of Estates, Liaison Officer (Parliament) Recruitment Rules, 2001, following entry shall be substituted :—

Column 5—‘Selection’ instead of ‘Selection-cum-seniority or Selection by merit’.

[F. No. A-12018/1/2000-Adm. B]

N.N. MATHUR, Addl. Director of Estates (Estt.)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 145.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपदा निदेशालय, संपदा सहायक निदेशक (लेखा) (भर्ती)(संशोधित) नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (अ) इन नियमों का नाम संपदा निदेशालय, संपदा सहायक निदेशक (लेखा) (भर्ती)(संशोधित) नियम, 2005 है।

(ब) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संपदा निदेशालय संपदा सहायक निदेशक (लेखा) भर्ती नियम 2001 की अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

स्तंभ 5-वरिष्ठता आधारित चयन या योग्यता आधारित चयन पद के स्थान पर चयन।

[मिसिल सं. ए-12018/1/2000-प्रशा. ख]

एन.एन. माथुर, अपर संपदा निदेशक (स्थापना)

New Delhi, the 13th April, 2005

G.S.R. 145.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Estates, Asstt. Director of Estates (Accounts) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2001.

1. (a) These rules may be called the Directorate of Estates, Asstt. Director of Estates, (Accounts) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2005.

(b) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Directorate of Estates, Asstt. Director of Estates (Accounts) Recruitment Rules, 2001, following entry shall be substituted :—

Column 5—'Selection' instead of 'Selection-cum-seniority or Selection by merit'.

[F. No. A-12018/1/2000-Adm. B]

N.N. MATHUR, Addl. Director of Estates (Estt.)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 146.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपदा निदेशालय, संपदा सहायक निदेशक (मुकदमा) (भर्ती)(संशोधित) नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (अ) इन नियमों का नाम संपदा निदेशालय, संपदा सहायक निदेशक (मुकदमा) (भर्ती)(संशोधित) नियम, 2005 है।

(ब) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संपदा निदेशालय, संपदा सहायक निदेशक (मुकदमा) भर्ती नियम 2001 की अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

स्तंभ 5—वरिष्ठता आधारित चयन या योग्यता आधारित चयन पद के स्थान पर चयन।

[मिसिल सं. ए-12018/1/2000-प्रशा. ख]

एन.एन. माथुर, अपर संपदा निदेशक (स्थापना)

New Delhi, the 13th April, 2005

G.S.R. 146.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Estates, Asstt. Director of Estates (Litigation) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2001.

1. (a) These rules may be called the Directorate of Estates, Asstt. Director of Estates, (Litigation) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2005.

(b) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Directorate of Estates, Asstt. Director of Estates (Litigation) Recruitment Rules, 2001, following entry shall be substituted :—

* Column 5—'Selection' instead of 'Selection-cum-seniority or Selection by merit'.

[F. No. A-12018/1/2000-Adm. B]

N.N. MATHUR, Addl. Director of Estates (Estt.)